।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

● वर्ष–5
● अंक–272
रायपुर, बुधवार
01 जुलाई 2026
● पृष्ठ–8
● मूल्य–3 रु.

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज–8>> शासकीय योजनाओं से मिल...

तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन

दुनिया को सही दिशा देना भारत की जिम्मेदारी : डॉ मोहन भागवत

बेंगलुरु। संसार को सही दिशा और समग्रता प्रदान करना भारत की जिम्मेदारी है। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंगचालक डॉ मोहन भागवत ने बेंगलुरु में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कही।

भारतीय शिक्षण मंडल (बीएसएम) द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन– भारतीय ज्ञान प्रणाली का समावेशन। इस अवसर पर मोहन भागवत ने बीएसएम की नयी आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया।

वैश्विक चुनौतियों का समाधान

सरसंघचालक जी ने कहा कि आज दुनिया जिन चुनौतियों से जूझ रही है, उसका समाधान भारत के समग्र और एकात्म चिंतन में निहित है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्थाएं केवल आंशिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जो आज के समय की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकती हैं। इस विश्व के कल्याण और सही दृष्टिकोण देने के लिए हमारी समग्र दृष्टि के आधार पर भारत की बात सुनी जानी चाहिए। यह समय की मांग है।

शास्त्रार्थ की परंपरा

डॉ भागवत ने कहा कि भारत अन्य संस्कृतियों या विचारों को गलत नहीं मानता। सभी समाज अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी धारणाएं बनाते हैं और उनका अपना महत्व है। भारत की विविधता को स्वीकार करने वाली दृष्टि सभी अनुभवों का स्वागत करती है। सत्या इतना विशाल है कि उसे किसी एक नजरिये में नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा मार्ग विवाद या बहस का नहीं बल्कि शास्त्रार्थ (विद्वतापूर्ण संवाद) का है, जिससे हर दृष्टिकोण के सार को ग्रहण किया जा सके। जहां अन्य विचार एकांगी रह जाते हैं, वहीं भारतीय चिंतन जीवन को पूर्णता और संतुलन प्रदान करता है।

शिक्षा में समग्रता का लक्ष्य

श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल का कार्य किसी सीमित दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक और सभ्यतागत मिशन का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएसएम सभी राजनीतिक दलों से पूरी तरह स्वतंत्र रहकर काम करता है। श्री भागवत ने स्वतंत्रता आंदोलन का उदाहरण दिया और याद दिलाया कि उस दौर के महापुरुषों ने भी शिक्षा और संस्कृति के रचनात्मक कार्यों को राजनीतिक संगठनों से अलग रखा था

कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति

बेंगलुरु में इस तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। समापन अवसर पर भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद जोशी, महासचिव डॉ भरतशरण सिंह मौजूद रहे। देश भर से आए 380 प्रतिनिधि, शिक्षाविद भी उपस्थित रहे।

टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले जेन-जी नहीं हो सकते: नितिन नवीन

हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि भारत का वास्तविक जेन–जी वह है जो अपने करियर का निर्माण करने के साथ–साथ देश के विकास में योगदान देता है, न कि वह जो संविधान, संस्कृति और देश की एकता पर सवाल उठाता है। तेलंगाना के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन ने शहर के बाहरी इलाके स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों से संवाद के दौरान यह बात कही। नितिन नवीन ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि %टुकड़े–टुकड़े गैंग% जैसी सोच रखने वाले, देश को बांटने वाले नारे लगाने वाले और भारत के संविधान, संस्कृति तथा देश की आत्मा पर सवाल उठाने वाले लोग भारत के त्द्द्ठ ँ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, %टुकड़े–टुकड़े गैंग वाले त्द्द्ठ ँ नहीं हो सकते%। नितिन ने ऐसे लोगों की पहचान करने और युवाओं को गुमराह करने की कोशिशों का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब

देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आजकल दुनिया भर में त्द्द्ठ ँ को लेकर काफी चर्चा होती है। कई देशों में युवाओं के आंदोलनों को त्द्द्ठ ँ आंदोलन कहा जाता है, लेकिन भारत के युवाओं की सोच और कार्यशैली अलग है। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा व्यवस्था विरोधी नहीं हैं, बल्कि देश के निर्माण और विकास में अपनी भूमिका निभाने में विश्वास रखते हैं।

छात्रों को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जो युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं, वही भारत के असली त्द्द्ठ ँ हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा नवाचार, तकनीक और ज्ञान के दम पर देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने जम्मू–कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय वहां के युवाओं की पहचान पत्थरबाजी से जुड़ गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिस्थितियां बदली हैं। अब कश्मीर के युवा खेलों में आगे बढ़ रहे हैं और रणजी ट्रॉफी जैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यह विरोध संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के युवा भारत को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें किसी विदेशी ताकत या भड़काऊ विचारधारा के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय युवा अपनी प्रतिभा, नवाचार और सकारात्मक सोच के बल पर विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को अपने सरगुजा प्रवास के दौरान विकासखंड उदयपुर स्थित रामगढ़ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस राम वाटिका में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेशवासियों के सुख–समृद्धि की कामना की, इसके साथ ही उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधारोपण किया।

बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर नया कानून लागू

■ **17% से घटाकर 7% हुआ कोटा, 66 वर्गों को मिलेगा लाभ**

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 2 पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इसके तहत ओबीसी आरक्षण को 17 से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है और बिना सर्वे शामिल किए गए 113 वर्गों को सूची से हटा दिया गया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को पिछड़े वर्गों से जुड़े दो अहम संशोधन विधेयकों को पारित किया गया है। ये विधेयक पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के साल 2012 के पुराने कानून में संशोधन करते हैं। हालांकि सदन में मतदान के दौरान विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी समेत बागी टीएमसी विधायकों के वॉकआउट कर दिया। हालांकि, ममता बनर्जी के प्रति वफादार रहने वाले धड़े ने सदन में रहकर इस संशोधन के पक्ष में मतदान किया। विधानसभा में पारित होने वाले इन 2 विधेयकों के नाम पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

को छोड़कर) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) संशोधन विधेयक 2026और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2026 हैं। इन नए विधेयकों के जरिए ओबीसी श्रेणी के तहत 66 वर्गों को आरक्षण दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आरक्षण के कोटे को पिछले 17 प्रतिशत से घटाकर अब 7 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही ओबीसी श्रेणियों का पुनर्गठन भी किया गया है। दूसरा विधेयक साल 1993 के उस कानून में संशोधन करता है जो पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के कामकाज को कंट्रोल करता है। सदन में विधेयकों के पक्ष में कुल 186 विधायकों ने वोट दिया, जबकि 17 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। छह विधायक मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी के अनुरोध पर स्पीकर रथिंद्र बोस ने वोटों के विभाजन का आदेश दिया था। नौशाद सिद्दीकी और बागी टीएमसी विधायक बिश्वनाथ दास ने पिछड़े वर्गों के सामाजिक न्याय के उल्लंघन का हवाला देते हुए इन विधेयकों का विरोध किया था।

प्रमुख समाचार

सीजेआई को 23 दलों और एक निर्दलीय सांसद ने लिखा पत्र

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को एक संयुक्त पत्र भेजा है। यह पत्र निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और चुनाव संबंधी अन्य मुद्दों पर है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने

सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। इस पत्र में विपक्षी गठबंधन ने एसआईआर के पालन के मामले में न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की है। विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में बताया कि 21 विपक्षी राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने 8 जून को हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

रामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रामपुर जिले में 690 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रदेश में विरासत का

अपमान होता था, कांवड़ यात्रा तक पर रोक लगाने की बातें होती थीं, सरकारी भर्तियों में वसूली होती थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था, धार्मिक आस्था और विकास तीनों को नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगे, फसाद और सांस्कृतिक विरासत के अपमान से जुड़ गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासन में कांवड़ यात्रा, होली, दीपावली, रामनवमी और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे धार्मिक आयोजनों में बाधाएं खड़ी की जाती थीं। आज प्रदेश में सभी पर्व बिना किसी रोक–टोक के पूरे उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही है।

राम मंदिर चंदा घोटाले पर गरजीं मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी का मामला बेहद गंभीर और चिंताजनक है। साथ ही, उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने

कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनका यह पोस्ट अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी के मामले में अयोध्या पुलिस और राज्य सरकार की ओर से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की चल रही जांच के बीच आया है। एक्स पर एक पोस्ट में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, गबन और हेराफेरी के बारे में रोज़ आ रही मीडिया रिपोर्टें बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं। ाम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे को लेकर भविष्य में ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए, देश भर के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में अपनाई जाने वाली अकाउंटिंग प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए।

खड़गे ही होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा में बतौर सदस्य कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो गया था. राज्यसभा सदस्य के रूप में खड़गे का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही विपक्ष के नेता का पद भी रिक्त हो गया था. अब खड़गे के राज्यसभा सदस्य के रूप में दूसरे कार्यकाल का

आगाज हो गया है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली. मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से लगातार दूसरी बार उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं. राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सदस्यता की शपथ दिलाई. मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदी में शपथ ली. इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, नेता सदन जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे.राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेने के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से विपक्ष का नेता भी चुन लिया गया।

आदित्य ठाकरे के करीबी ने थामा शिंदे का दामन

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। आदित्य ठाकरे के करीबी और मुंबई की राजनीति में प्रभावशाली नेता माने जाने वाले सचिन अहीर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। अहीर ने शिंदे गुट में शामिल होने

के तुरंत बाद महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए महायुति उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस घटनाक्रम को महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर–3 के तौर पर देखा जा रहा है। सचिन अहीर का शिंदे गुट में जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें आदित्य ठाकरे का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता रहा है। हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) के नौ में से छह सांसद शिंदे गुट में शामिल हुए थे। अब अहीर के पाला बदलने से उद्धव ठाकरे की संगठनात्मक ताकत और रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। शिंदे गुट का दावा है कि आने वाले दिनों में उद्धव खेमे के कई और विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। सचिन अहीर सिर्फ शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता ही नहीं थे।

भारत और खाड़ी संकट का आर्थिक प्रभाव: सब कुछ स्थिर और सामान्य रहा

वी. अनंत नागेश्वरन

जब फरवरी के अंत में हवाई हमलों के कारण हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद हो गया – ऐसा समुद्री मार्ग जिससे होकर दुनिया के कच्चे तेल का करीब एक–पांचवां हिस्सा और भारत के कच्चे तेल और खाना पकाने के गैस का अधिकांश हिस्सा गुजरता है — तो भारत के लिए कहानी पहले ही लिखी हुई लग रही थी। एक ऐसा देश, जो अपने कच्चे तेल का दस में से नौ हिस्सा और आधे से ज्यादा खाना पकाने के गैस का खाड़ी से आयात करता है, उसके लिए आम तौर पर यही उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगेंगी, रसोई में गैस खत्म हो जाएगी, रुपये की कीमत गिरेगी और डॉलर के लिए होड़ मचेगी। लगभग चार महीने बाद, जब जलडमरूमध्य फिर से खुल गया और कच्चे तेल की आपूर्ति अपने संकट–पूर्व स्तर के करीब पहुँच गयी, तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। एक भी रिटेल आउटलेट बंद नहीं हुआ। जिस भी परिवार को सिलेंडर चाहिए था, उसे सिलेंडर मिल गया।

भारत को न तो 1991 जैसे और न ही 2013 जैसे हालात का सामना करना पड़ा। व्यापक आर्थिक स्थिरता बनी रही। यह कोई संयोग नहीं था और न ही यह सिर्फ़ किस्मत की बात थी। यह एक ऐसे सरकार का काम था, जिसने वही तरीका अपनाया, जो उसने महामारी के समय अपनाया था – जानबूझकर और धीरे–धीरे कदम उठाना, एक ही बार में कोई बड़ा या नाटकीय बदलाव करने के बजाय एक उपाय के ऊपर दूसरे उपाय को जोड़ना। पहली प्राथमिकता घर–परिवार थे। इस पूरी अवधि के दौरान, एक भी रिटेल आउटलेट का स्टॉक खत्म नहीं हुआ और हर रसोईघर में सिलेंडर मौजूद रहा। आयात से जुड़ी लागत के कारण 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर कीकीमत 1,600 रुपये से ऊपर चली गई थी, फिर भी घरों के लिए इसकी कीमत 900 रुपये के आसपास ही रखी गई और सबसे गरीब लोगों के लिए तो यह कीमत और भी कम थी। महामारी के शुरुआती महीनों की यादें एक सबक थीं, जब प्रवासी मजदूरों में मची घबराहट के कारण गांवों की ओर लौटने वालों की लहर चल पड़ी थी। वाणिज्यिक और थोक उपयोगकर्ताओं को घरों की जरूरत को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले ईंधन के मामले में,

सरकार ने इसका बोझ खुद उठाने का फ़ैसला किया, न कि इसे आम लोगों पर डाला। सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में दस रुपये प्रति लीटर की कटौती की, जिससे उसे लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ, इसके अलावा विमानन ईंधन पर भी बोझ कम किया गया। इसके बाद तेल विपणन कंपनियों ने दो महीने से ज़्यादा समय तक पंप पर कीमतें स्थिर रखीं और फिर एक बार मामूली बदलाव किया। इसके पीछे की वजह साफ़ है– ऐसी अनिश्चितता के समय में, सिर्फ़ सरकार के पास ही जोखिम उठाने के लिए ज़रूरी बैलेंस शीट और समय होता है; और इसने परिवारों और कंपनियों पर असर डालने के बजाय राजकोषीय खाते पर बोझ डालने का विकल्प चुना।

एयरलाइंस के लिए खास समर्थन तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण–गारंटी योजना, कोविड के दौर में अपनाए गए खास और असरदार उपायों के मॉडल पर ही आधारित थीं। कीमत में राहत के पीछे आपूर्ति की मजबूत स्थिति थी। घरेलू रिफाइनरियों ने एक हफ्ते मे ही रसोई गैस का उत्पादन आधा बढ़ा दिया, जिससे आयात से आने वाली गैस की कमी काफी हद तक पूरी हो गई। भारत ने जल्दी ही अपने स्त्रोतों का विस्तार किया, अमेरिका और रूस से खरीद बढ़ायी और नए आपूर्तिकर्ता देश जोड़े, ताकि जलडमरूमध्य से होकर कम ऊर्जा आये; साथ ही रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखने के लिए ज़रूरी छूट भी हासिल कर ली। सरकार ने लंबी अवधि के लिए भी कदम उठाए– घरों को सिलेंडर के बदले पाइप से गैस पहुँचाना, कोयले गैसीकरण कार्यक्रम, ईथेनॉल मिश्रण को और बढ़ावा देना तथा प्रधानमंत्री कीसंयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान रणनीतिक तौर पर कच्चा तेल भंडारण पर सहमति। भारत उन कुछ देशों में से एक था, जिसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाजों की संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपना कार्गो लाना जारी रखा। बाहरी खातों को भी उतने ही धैर्य के साथ संभाला गया। सरकार ने सरकारी कर्ज़ की विदेशी संस्थागत खरीद पर लगी रोक और पूंजीगत लाभ टैक्स हटा दिए और पूर्ण पहुँच रूट के तहत प्रतिभूतियों का दायरा बढ़ाया, जिससे बॉन्ड मार्केट में पैसा आया। एक नई गैर–निवासी डॉलर जमा योजना से काफी बड़ी राशि में डॉलर आने की उम्मीद है। सालों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते धीरे–धीरे अपने काम कर रहे थे– अप्रैल और मई 2026 के दौरान गैर– तेल, गैर–रत्न–आभूषण के अलावा वस्तु और सेवाओं का निर्यात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। प्रमुख आंकड़े भरोसा दिलाते हैं।

समाचार पचीसा
रायपुर, बुधवार 01 जुलाई 2026

परिक्रमा पथ विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन

चक्काजाम से थमा ट्रैफिक, प्रशासन ने बदला रूट

डोंगरगढ़। 55 करोड़ रुपाए की बहुचर्चित परिक्रमा पथ परियोजना के विरोध में कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन ने मंगलवार को डोंगरगढ़ की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित कर दी। शहर के हाईस्कूल चौक पर किए गए चक्काजाम के चलते खैरागढ़, चिचोला, महाराष्ट्र और राजनांदगांव की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति ऐसी बन गई कि प्रशासन को तत्काल वैकल्पिक मार्ग (रूट डायवर्ट) लागू कर वाहनों की आवाजाही सुचारू कराने की व्यवस्था करनी पड़ी।

आंदोलन में विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, नवाज खान, कांग्रेस नेता विजयराज सिंह, संध्या देशपाण्डे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और परिक्रमा पथ परियोजना का विरोध कर रहे प्रभावित किसान शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं परिक्रमा पथ परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग दोहराई।

कांग्रेस का आरोप है कि शहर की सबसे बड़ी जरूरत बाईपास और बेहतर यातायात व्यवस्था है, लेकिन प्रशासन इन मुद्दों को नजरअंदाज कर करोड़ों रुपये की परिक्रमा पथ परियोजना को प्राथमिकता दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चार प्रमुख मांगें रखते हुए परिक्रमा पथ रद्द करने, बाईपास निर्माण शुरू करने, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने तथा शहर के तीन प्रमुख चौकों पर स्थायी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की मांग की।

चक्काजाम के कारण मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लगने से आम नागरिकों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया और वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को निकालकर यातायात सामान्य करने का प्रयास किया। परिक्रमा पथ परियोजना को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब किसानों की आपत्तियों से आगे बढ़कर बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है।

सीईओ के तबादले की मांग पर अड़े सरपचों ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

मोहला-मानपुर। छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में जिला सरपंच संघ और स्थानीय प्रशासन के बीच छिड़ा विवाद गहराता जा रहा है। निर्माण कार्यों के भुगतान में कथित कमीशनखोरी, अनावश्यक देरी और अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीनों विकासखंडों के सरपंचों ने जिला पंचायत सीईओ के तबादले की मांग तेज कर दी है। सरपंचों ने मांग पर जल्द निर्णय नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। सरपंचों ने जिला पंचायत सीईओ के अन्यत्र स्थानांतरित के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया है। सरपंच संघ ने प्रशासनिक अफसरों की कार्यशैली को प्रशासनिक आतंकवाद करार देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से भी न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने मांग की है कि सरपंचों को इस प्रशासनिक आतंकवाद से छुटकारा दिलाए। दरअसल, जिला सरपंच संघ के बैनर तले सरपंचों ने सप्ताह भर पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। लेकिन इस दौरान कलेक्टर के मुलाकात नहीं करने पर नाराज सरपंच संघ ने 24 जून को प्रदेश स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभा का बहिष्कार भी कर दिया था। इसका असर जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों में देखने को मिला, जहां कई स्थानों पर सरपंचों की अनुपस्थिति में ग्राम सभाएं आयोजित हुईं, जबकि कुछ पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन ही नहीं हो सका।

इसी विवाद के बीच 29 जून को कलेक्ट्रेट परिसर में जिला सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल और कलेक्टर के बीच बैठक हुई। बैठक के दौरान सरपंच संघ ने लिखित ज्ञापन सौंपते हुए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भारती चंद्राकर का स्थानांतरण करने की मांग रखी। हालांकि कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह विषय उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वे इस मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। कलेक्टर से चर्चा में ठोस समाधान नहीं निकलने के बाद सरपंच संघ ने मोहला स्थित सामुदायिक भवन में फिर से बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो जिलेभर के सरपंच आंदोलन को और तेज करेंगे। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में सभी सरपंच सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। मामले के संबंध में जिला पंचायत सीईओ भारती चंद्राकर से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी कहने से इनकार कर दिया। सरपंच संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह गैर-राजनीतिक है। संघ ने राजनीतिक दलों और नेताओं से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर बयानबाजी कर आंदोलन का राजनीतिकरण न करें, क्योंकि सरपंच अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम हैं।

कोलियारी में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल

50 से अधिक घर खाली करने के नोटिस पर भड़के ग्रामीण, गांव में राजस्व टीम को घेरा

धमतरी। रायपुर के नकटी गांव के बाद धमतरी के कोलियारी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर मंगलवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। 50 से अधिक मकानों को खाली करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद ग्रामीणों और राजस्व टीम के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हुई। मौके पर कुछ समय के लिए स्थिति गर्मा गई।ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी तरह गलत है। उनका कहना है कि एक निजी संस्थान को जमीन उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग दबाव बनाकर लोगों को उनके घरों से हटाने की कोशिश कर रहा है। धमतरी में भी रायपुर के नकटी गांव जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग का कहना है कि संबंधित भूमि पर 50 से अधिक मकान अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के तहत संबंधित लोगों को घर खाली करने का नोटिस और अल्टीमेटम दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और कार्रवाई का विरोध जताने लगे। इस दौरान राजस्व अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। राजस्व अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संबंधित लोगों को जल्द से जल्द अतिक्रमित भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत पहुंचे मनेंद्रगढ़

एमसीबी। 16 जून, दिन मंगलवार को रेत खनन में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बीजेपी नेता की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद से लगातार सियासत जारी है। विपक्ष के बाद अब करणी सेना ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है।

सोमवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ। राज शेखावत मनेन्द्रगढ़ पहुंचे। राज शेखावत ने नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है और कार्रवाई अपेक्षित स्तर पर नहीं हुई है। डॉ। राज शेखावत ने कहा कि 16 जून की रात कार में आग लगाए जाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। करणी सेना ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। करणी सेना ने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है।

करणी सेना ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

सुकमा के दुर्गम इलाकों में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

सुकमा। पल्स पोलियो अभियान का आज तीसरा और अंतिम दिन है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन तीन दिनों में सुकमा जिले के सभी गांवों में पहुंचकर बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य लगभग पूरा कर चुकी है। जिन गांवों में कभी गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, वहां आज बच्चे शोर मचाते हुए गांव वालों को बता रहे हैं कि नर्स दीदी आई हैं और बच्चों को दवा पिला रही हैं। पल्स पोलियो अभियान के तहत गांव-गांव पहुंचकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता पांच साल तक के बच्चों को दवा पिला रहे हैं। कभी माओवाद का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले पूवर्ती गांव में आज बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। जिस गांव का नाम कभी नक्सली घटनाओं और सुरक्षा चुनौतियों के कारण चर्चा में रहता था, वहां अब स्वास्थ्य कर्मियों की दस्तक सुनाई दे रही है। यह दृश्य बताता है कि अब विकास की किरण उन इलाकों तक भी पहुंच रही है, जो वर्षों तक मुख्यधारा से कटे रहे। सुकमा कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर जिले में विशेष पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के करीब 39 हजार बच्चों को चिन्हित कर पोलियो की जीवनरक्षक खुराक पिलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार दूरस्थ और संवेदनशील गांवों तक पहुंचकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा कवच से वंचित न रहे। इस अभियान की सबसे भावुक तस्वीर पूवर्ती से सामने आई है। जहां कभी सरकारी कर्मचारी सुरक्षा के बिना जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वहीं आज स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेखौफ होकर गांव की गलियों में घूम रहे हैं। वे हर घर तक पहुंच रहे हैं, बच्चों का हालचाल पूछ रहे हैं और उन्हें पोलियो की दो बूंद पिलाकर स्वस्थ भविष्य की नींव रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक पूवर्ती जैसे संवेदनशील गांव में 170 बच्चों को पोलियो की दवा पिला चुकी है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है, जो वर्षों बाद शासन, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच फिर से मजबूत हुआ है।

एक समय ऐसा था जब पूवर्ती का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय का माहौल बन जाता था। गांव तक पहुंचना कठिन था और सरकारी योजनाओं का लाभ

भिलाई टाउनशिप बचाने सड़क पर उतरे विधायक

भिलाई में आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद रहवासियों के समर्थन में देवेंद्र यादव सड़क पर उतरे हैं. कहा किसी कीमत पर नहीं उजड़ने देंगे बसाहट

भिलाई। भिलाई टाउनशिप में बीएसपी प्रबंधन ने कई लोगों को मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है।नोटिस मिलने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोगों की परेशानी को देखते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव प्रभावित परिवारों के समर्थन में उतरे हैं।विधायक देवेंद्र यादव ने मंगलवार को नोटिस पा चुके परिवारों से मुलाकात की।सेक्टर 2 में उन्होंने अपने जनसमर्थन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उनके समर्थन में नजर आए। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भिलाई की बसावट को खत्म करने के लिए सुनियोजित तरीके से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रिटेंशन स्कीम के तहत मकान खाली कराने का प्रयास किया गया। अब लीजधारकों तथा लाइसेंसधारकों को हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर भिलाई टाउनशिप की बसावट खत्म नहीं होने दी जाएगी।मैं उन सभी परिवारों से मिलेंगे जिन्हें बीएसपी की ओर से नोटिस मिला है और उनसे समर्थन पत्र भी लिया जाएगा। इन समर्थन पत्रों के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय इस्पात मंत्री से मुलाकात कर मामले को उठाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को बड़े जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से संचालित होगा।

देवेंद्र यादव ने कहा कि इस पूरे मामले से 10 हजार से अधिक परिवार प्रभावित हो सकते हैं।उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में टाउनशिप के बड़े हिस्से को खाली कर निजी संस्थाओं या बिल्डरों को सौंपने की योजना हो सकती है। विधायक ने कहा कि भिलाई केवल एक औद्योगिक शहर नहीं, बल्कि देशभर के लोगों की साझा संस्कृति और वर्षों पुरानी बसाहट की पहचान है, जिसे बचाने के लिए वे आखिर दम तक लड़ाई लड़ेंगे।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

लिव-इन पार्टनर नहीं लगा सकता दुष्कर्म का आरोप

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि लंबे समय तक लिव-इन संबंध में रहने वाले वयस्कों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से माने जाएंगे। पुरुष द्वारा बाद में शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं माना जाएगा। यह फैसला एक महिला की अपील पर आया है। न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने यह निर्णय दिया। पीठ ने कहा कि लिव-इन संबंधों में जोड़े शादी की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि, यह अकेले साबित नहीं करता कि शारीरिक संबंध केवल शादी के वादे पर आधारित था। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक चले लिव-इन संबंध में यह अनुमान लगाया जाएगा। इसमें पक्षों ने स्वेच्छा से संबंध चुना, जिसके परिणामों से वे अवगत थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। अदालतों को ऐसे मामलों की जांच करते समय संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। इसके बजाय, संबंध की अवधि और पक्षों के आचरण पर विचार करना चाहिए।

कर्वधा के नवीन बाजार में हनुमान जी का चांदी का मुकुट चोरी

कबीरधाम। शहर में चोरों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। चोर अब मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। सोमवार को रेवाबंध तालाब के पास नवीन बाजार हनुमान मंदिर में चोरों ने सेंधमारी की। चोरों ने यहां से भगवान का चांदी का मुकुट चुरा लिया। चोरी गया मुकुट काफी कीमती थी और 25 से 30 तोले चांदी में बना था। चोरी की इस वारदात से स्थानीय लोगों और भक्तों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोगों को मुताबिक बीते रात सात बजे मंदिर में नियमित आरती और पूजा-पाठ संपन्न हुआ था। उस समय तक सब कुछ सामान्य था। करीब आठ बजे जब मंदिर का दरवाजा बंद करने पुजारी और अन्य लोग पहुंचे तो भगवान बजरंगबली की प्रतिमा से चांदी का मुकुट गायब मिला। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस अन्य साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है।

झूठे केस में फंसाने वाली महिला हुई गिरफ्तार

एमसीबी। लोगों को झूठी शिकायतों के आधार पर गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देने वाली महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने शिकायतों के आधार पर दर्ज की है। महिला पर आरोप है कि वो झूठी शिकायतों के आधार पर लोगों को फंसाने की धमकी दिया करती है। जो लोग धमकी से डर जाते हैं उनसे वो अनुचित लाभ वसूलती है। मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनेन्द्रगढ़ से अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद की। पुलिस के अनुसार, आरोपिया ने अपने पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए अलग-अलग अधिकारियों के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की थी। पुलिस ने शिकायतों की विस्तृत जांच करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों की सिलसिलेवार जांच की। तथ्य के परीक्षण के दौरान लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी और शिकायतें झूठी एवं भ्रामक पाए जाने की बात सामने आई।

रेलवे का तोहफा, रथयात्रा पर गोंदिया-पुरी के बीच विशेष ट्रेन

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रथयात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोंदिया और पुरी के बीच चलेगी। ट्रेन संख्या 08801/08802 रथयात्रा स्पेशल जुलाई 2026 में कुल आठ फेरे लगाएगी। यह विशेष ट्रेन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। गोंदिया-पुरी रथयात्रा स्पेशल (08801) 02, 09, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से 13ः30 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन 10ः00 बजे पुरी पहुंचेगी। इसी प्रकार, पुरी-गोंदिया रथयात्रा स्पेशल (08802) 03, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से 13.00 बजे प्रस्थान करेगी। यह अगले दिन 07.00 बजे गोंदिया पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह विशेष ट्रेन कुल चार-चार फेरे लगाएगी। ट्रेन में कुल 20 आईसीएफ कोच होंगे। इन कोचों में दो दिव्यांग अनुकूल सह गार्ड, दस शयनयान, तीन तृतीय एसी और दो द्वितीय एसी कोच शामिल हैं। यह सुविधा यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी। गाड़ी संख्या 08801 गोंदिया से 13.30 बजे प्रस्थान करेगी।

उज्जैन की तर्ज पर महानदी किनारे विकसित होगा धाम

धमतरी। रुद्रेश्वर कॉरिडोर का निर्माण महानदी के किनारे प्रस्तावित है। रुद्रेश्वर कॉरिडोर को विकसित करने और उसे पर्यटन स्थल की पहचान देने के काम शुरू हो चुका है। इसकी कड़ी में जिला प्रशासन ने एक एआई आधारित विजन वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भविष्य में विकसित होने वाले रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर की भव्य और आकर्षक तस्वीर दिखाई गई है। वीडियो में महानदी के तट पर विशालकाय महादेव प्रतिमा, भव्य घाट, गंगा आरती, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर स्वागत द्वार, आकर्षक गार्डन, चौड़ी सड़कें, मंदिर परिसर की सुंदर सजावट और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का शानदार दर्शन कराया गया है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि यह वीडियो रुद्रेश्वर कॉरिडोर के प्रारंभिक आर्किटेक्चरल विजन को दर्शाता है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि परियोजना पूरी होने के बाद रुद्रेश्वर धाम किस स्वरूप में नजर आएगा। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिले को पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी।

कोसरंडा हूलतराई पुल निर्माण के गुणवत्ता की जांच

विधायक विक्रम उसेंडी ने किया निरीक्षण

कांकेर। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित मांग कोसरंडा-हूलतराई पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने विधायक विक्रम देव उसेंडी पहुंचे। पुल का निर्माण अब अंतिम चरण में है और इसे जल्द पूरा करने के लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और बताया कि यह पुल क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांगों में शामिल था।

उन्होंने कहा कि पुल निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है और कार्य को जल्द पूरा करने के लिए ठेकेदार को फोन पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।इस दौरान विक्रम उसेंडी ने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है और दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। निरीक्षण के दौरान विधायक उसेंडी ने आंगनबाड़ी भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने क्षेत्र में पेयजल समस्या और सामुदायिक भवन शेड निर्माण की मांग उनके सामने रखी।

विधायक ने कहा कि इन मांगों पर भी प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। विधायक उसेंडी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन और सुरक्षा बलों के प्रयासों से बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद काफी हद तक समाप्त हुआ है। इसके परिणामस्वरूप अब दूरस्थ इलाकों में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। विधायक ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के समग्र विकास और ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आने वाले समय में कई नई विकास परियोजनाएं धरातल पर दिखाई देंगी

धर्मांतरित परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान, ग्रामीणों ने घर से बाहर निकाला सामान

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भरण्डा के बाद खड़का गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। धर्मांतरित परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान जारी किया गया है। आदिवासी सामाज के लोगों ने धर्मांतरित परिवारों के घरों से सामानों को बाहर निकाल दिया है। इसके बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल, पूरा मामला खड़का गांव का है। जहां आदिवासी समुदाय और धर्मांतरित परिवारों के बीच भारी विवाद की स्थिति बनी हुई है। ईसाई धर्म अपनाने वाले दो परिवारों पर गांव छोड़ने का दबाव बनाते हुए उनके घरों से सामान बाहर निकाल दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि धर्मांतरित परिवार गांव के सामाजिक कार्यक्रमों में अन्य ग्रामीणों की तरह चंदा दें और आदिवासी देवी-देवताओं और पारंपरिक रीति-रिवाजों को मानें। वहीं प्रभावित परिवारों का कहना है कि वह साल में केवल एक बार ही चंदा देंगे, लेकिन आदिवासी धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं करेंगे। इसको लेकर तनाव बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कोई भी अपिहार्य घटना न हो। मामले में प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि हाल ही में भरण्डा गांव में आदिवासी ग्रामीणों ने 26 धर्मांतरित परिवारों को गांव छोड़ने के लिए कहा था। उनपर दबाव बनाया जा रहा था कि ईसाई धर्म अपना चुके लोग पुरानी संस्कृति में लौटें या फिर गांव छोड़ दें।

संक्षिप्त समाचार

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक : शिकायत पर प्रमुखता से कार्रवाई करेगा प्रशासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष द्वारा नए कानून के लागू न होने और पुराने एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने के आरोपों पर मंत्री ने साफ किया कि इस तरह की कोई शिकायत होगी, तो प्रशासन प्रमुखता से ध्यान देकर कार्रवाई करेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के लिए चिंतित है। बहुत जल्दी लागू होगा। भाजपा की सरकार में अच्छे-अच्छे लोग कभी राम मंदिर का नाम नहीं लेते थे वे भी मंदिर जाना शुरू कर दिए। समय के अनुसार उनका परिवर्तित चेहरा दिखाई दे रहा है और उनके मुख से ऐसी बाते की जा रही ये समय का तकाजा है।

सरोना फ्लाईओवर में पलटा 6 ट्रैक्टरों से लदा ट्रेलर, कोई जनहानि नहीं

रायपुर। सरोना फ्लाईओवर पर मंगलवार

सुबह सड़क हादसा हो गया। 6 ट्रैक्टरों से लदा ट्रेलर सरोना ब्रिज से गुजरते समय बेकाबू होकर पलट गया। हादसे के बाद दुर्ग-रायपुर रोड पर यातायात बाधित हो गया और लंबा जाम लग गया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। ट्रेलर पलटते ही सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और अन्य टीमें मौके पर पहुंचीं और क्रेन की मदद से राहत और हटाने का कार्य शुरू किया गया। करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद ट्रेलर को हटाकर यातायात सामान्य किया गया हादसे में ट्रेलर में लदे ट्रैक्टरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, लेकिन चालक सुरक्षित है। शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपट गिरफ्तार फरार चल रहा था

रायपुर। रायपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर गौरव हेपट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी अलग से केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, डीडी नगर थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में गौरव हेपट घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। लंबित गंभीर मामलों की समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और डीडी नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने उसकी तलाश तेज कर दी।

घरजियाबंधान जलाशय योजना के लिए 51.6 करोड़ रूपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा जशपुर जिले के विकासखंड-पत्थलगांव की घरजियाबंधान जलाशय योजना के कार्यों के लिए 51 करोड़ 6 लाख 29 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। इस सिंचाई योजना के निर्माण होने पर क्षेत्रीय किसानों को खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए करीब 2064 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। योजना के निर्माण कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

रायपुर में 5 जुलाई को होगा मेगा रक्तदान महोत्सव, 500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य

रायपुर। मानव सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मोपॉलिटन, रोटरी क्लब ऑफ कॉस्मो दिवास, रोटरी क्लब ऑफ रायपुर इन्फिनिटी एवं इनर व्हील क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मोपॉलिटन के संयुक्त तत्वावधान में 5 जुलाई रविवार को मेगा रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह रक्तदान शिविर सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक विमतारा हॉल, शंकर नगर, रायपुर में आयोजित होगा। इस अभियान में डीकेएमएस फाउंडेशन इंडिया, आईडीआईएई (रायपुर ब्रांच) एवं आशीर्वाद ब्लड सेंटर का विशेष सहयोग रहेगा। आयोजकों ने शहरवासियों, युवाओं, सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं से इस महाअभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। साथ ही कहा कि आपका एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद मरीज को नया जीवन दे सकता है। रक्तदान- महादान। आइए, मानवता की इस सेवा में सहभागी बनें और किसी के जीवन में नई उम्मीद बनें। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य 500 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह करना है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके।

नकटी गांव में कार्रवाई पर सियासत, भूपेश बघेल ने कहा- भाजपा नेताओं में अनबन

आपस में लड़ाने की कोशिश न करें, अपनी पार्टी पर दें ध्यान: साव

रायपुर। नकटी गांव में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को पहले यह पता नहीं था कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मुख्यमंत्री के बीच अनबन है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर लोग ओपी चौधरी के घर गए होते तो उनके मकान नहीं टूटते, लेकिन लोग बृजमोहन अग्रवाल के घर गए, इसलिए अगले ही दिन उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया।

मंगलवार को मीडिया से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल के इस बयान पर पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल अपनी पार्टी पर ध्यान दें और भाजपा के नेताओं को आपस में लड़ाने की कोशिश न करें।

इसके अलावा उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अलंकरण, धर्मांतरण, कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और ग्रामीण विकास से जुड़ी नई व्यवस्था पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक को लेकर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अलंकरण से संबंधित बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में खिलाड़ियों के सम्मान और खेलों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी तथा आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ साहू समाज की बैठक में शामिल होने के बाद उपमुख्यमंत्री ने बताया कि समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न सामाजिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में समाज को धर्मांतरण के मुद्दे पर जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया गया।

कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के बाद पार्टी के आक्रामक रुख अपनाने संबंधी सवाल पर अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर नहीं, बल्कि अपने नेताओं के बीच संघर्ष में अधिक व्यस्त है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि आक्रामक होगी तो वह एक-दूसरे के खिलाफ होगी। उनके अनुसार पार्टी के पास जनता के हित में कोई स्पष्ट सोच नहीं है और केवल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से स्थिति नहीं बदलने वाली।

ग्रामीण विकास से जुड़ी नई व्यवस्था (वीबी जी राम जी) को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर राष्ट्रीय निर्णय का विरोध करने की आदत बना चुकी है।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इससे ग्रामीण श्रमिकों को अधिक दिनों तक रोजगार उपलब्ध होगा, ग्राम पंचायतों के अधिकार बढ़ेंगे और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य कराए जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री साय की पहल से किसानों को बड़ी राहत

पूर्व वर्ष की तरह मिलेगा एकमुश्त यूरिया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने और खेती को अधिक सुगम बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में खरीफ सीजन 2026 के लिए जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया वितरण पर लागू 80 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब किसानों को खरीफ 2025 की भांति उनकी पात्रता के अनुरूप एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा।

उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा ने बताया कि खरीफ 2026 में किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के अनुरूप यूरिया वितरित किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहेगा तो किसानों को एकमुश्त यूरिया प्रदान किया जाएगा। किसी समिति में स्टॉक की कमी होने पर शेष मात्रा यूरिया उपलब्ध होते ही किसानों को वितरित कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि शासन के इस निर्णय से किसानों को बार-बार समिति के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और खरीफ सीजन में आवश्यक उर्वरक समय पर उपलब्ध होने से कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सकेंगे। इससे किसानों को खेती की तैयारी में सुविधा मिलेगी तथा समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से फसल उत्पादन को भी गति मिलेगी।

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें : मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का कंडिकावार शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से अंकेक्षण रिपोर्ट दिया जाना आवश्यक है। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने पर बल दिया गया।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में अब तक किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना एवं बजट का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निर्माण हेतु विस्तार से चर्चा हुई। सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग के लिए भी चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के विस्तार हेतु अन्य योजनाओं से निश्चित विकास निधि के निर्धारण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में मनरेगा योजना को संशोधित नवीन योजना वीबीजीरामजी में सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान का अवलोकन, आत्मसात करने के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा सहित अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के कार्यों के संपादन हेतु विभिन्न पदों को नियमानुसार भरने के लिए आवश्यक नियमों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अनुमोदन किया गया।

खुले गड्ढों से बच्चों को बचाने के लिए नगरीय प्रशासन तत्काल करे व्यवस्था : डॉ. वर्णिका

- **बारिश में खुले ग ों का बढ़ा खतरा, नगरीय प्रशासन को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंगलवार को नगरीय प्रशासन विभाग, जिला कलेक्टर व नगरीय निकायों के उच्चाधिकारियों को एक बेहद सख्त अनुशंसा भेजते हुए लेख किया है कि आयोग के समक्ष इस प्रकार के प्रकरण देखने में आये है, जिसमें कि कॉलोनी में निर्माणाधीन गड्ढे खुले होने, सड़कों पर गड्ढे खुले होने अथवा बारिश में नालियों के ढक जाने के कारण उसमें बच्चे गिर पड़े हैं एवं उनके जीवन का अंत हो गया है।

आयोग ने इसे बेहद दु:खद माना है एवं आयोग द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 तथा सहपठित धारा 15 के तहत बच्चों के जीवन के अधिकार की रक्षा को देखते हुए यह अनुशंसा क्रमांक आर-191/30.06.2026 की है कि, नगरीय क्षेत्र में तत्काल एक सर्वेक्षण अभियान चलाकर ऐसे खुले गड्ढों, नालियों या निर्माणाधीन स्थलों को चिन्हाँकित कर लिया जाये और उन्हें या तो भर दिया जाये अथवा उनके चारो ओर सुरक्षा कवच के रूप में बल्ली आदि से बाड़ी लगा दी जाये जिससे बच्चे उसमें न गिरने पायें, समस्त निर्माण एजेन्सियों तथा आवासीय कॉलोनियों को यह निर्देश जारी किये जाये कि किसी भी प्रकार से निर्माण के लिए खोदे गये नींव स्थल/कॉलम स्थल/अन्य कारणों से खोदे गये गड्ढों के चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाकर इस प्रकार बंद करना कि वहाँ बच्चे आवाजाही करते समय न गिरें यह सुनिश्चित करें, संवेदनशील निर्माणाधीन स्थलों पर निर्माण एजेन्सियाँ एक चौकीदार/सुरक्षाकर्मी भी इस हेतु तैनात करें जो बच्चों को जोखिम से बचाने में सहायक हो सके। अनुशंसा में यह भी लेख है कि बारिश में खेलते समय या शाला आते जाते समय पैदल चलते बच्चों को बारिश के छोटे गड्ढे अथवा बड़े गड्ढों में अंतर समझ में नहीं आता है एवं बच्चों को अनजाने में ही जान का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष स्तर से पर्याप्त निर्देश प्रसारित किये जायें एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर व नगरीय निकाय के उच्चाधिकारी तत्काल इस विषय पर पहल करें एवं इसे नियमित साप्ताहिक समय सीमा के पत्रों पर कार्यवाही की समीक्षा के विषय के रूप में शामिल किया जाये। आयोग ने उक्तानुसार अनुशंसा पर कार्यवाही करते हुए निर्देश प्रसारित कर आयोग को दिनांक 07 जुलाई 2026 तक लिखित में अवगत कराने का भी लेख किया है।

8 से 14 जुलाई तक इंडोर स्टेडियम में होगी देवकीनंदन ठाकुर की श्रीमद्भागवत कथा

रायपुर। भोपाल में हुई कथा के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कथा आयोजकों से निवेदन किया था कि बिना तिलक के श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए और इसका पालन करते हुए अंतरराष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी एवं प्रदेश महामंत्री शिवरतन गुप्ता ने 8 से 14 जुलाई तक राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में श्रीमद् भागवत कथा में बिना तिलक के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्रद्धालु चाहे तो कथा स्थल या अपने घर, मंदिर से तिलक लगाकर प्रवेश कर सकते है।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए योगेश अग्रवाल ने बताया कि कथा रोजाना दोपहर को 3.30 से शाम को 7.30 बजे तक होगी और इसका सीधा प्रसारण आस्था टीवी और महाराज श्री के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। कथा स्थल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण कर दिया जाएगा क्योंकि कथा समाप्ति के बाद प्रसाद लेने के लिए भगदड़ की स्थिति निर्मित ना हो। कथा स्थल में प्रवेश पूरी तरह से निशुल्क रहेगा और इसके लिए चार प्रवेश द्वार वृंदावन, बरसाना, नंदगांव व गोकुल धाम बनाए गए है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर 7 जुलाई की शाम को 4 बजे नई दिल्ली से विमान के द्वारा राजधानी रायपुर की पावन धरती पर प्रवेश करेंगे जहां आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। 8 जुलाई को कथा प्रारंभ होने से पहले प्रातः 9 बजे विशाल कलश यात्रा महामाया मंदिर से प्रारंभ होकर सदानी चौक, बुढ़ापारा होते हुए इनडोर स्टेडियम पहुंचेगी। कलश यात्रा में राउत नाचा, बैंड पार्टी व ढोल नगाडे एवं राधे कृष्ण की सजीव झांकी के साथ 5000 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर पैदल चलेंगी, कलश यात्रा का विभिन्न समाज द्वारा स्वागत किया जाएगा।

अग्रवाल ने बताया कि कथा श्रवण करने के लिए, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह एवं मंत्री, सांसद व विधायक सहित पूरे प्रदेश के श्रद्धालु शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान संजय चौधरी, राजेश अग्रवाल, सुभाष साहू, अशोक गुप्ता, राजीव अवस्थी, दीपक गुप्ता, विनोद पहुजा, सुब्रत घोष, नवीन लोढ़ा उपस्थित रहे।

धर्मांतरण के मुद्दे पर साहू समाज चलाएगा प्रदेश में जनजागरण अभियान

रायपुर। धर्मांतरण के मुद्दे पर साहू समाज ने प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। इस संबंध में रायपुर के टिकरापारा स्थित साहू समाज भवन में करीब छह घंटे तक मैराथन बैठक चली। बैठक में समाज के पदाधिकारियों के साथ भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री एवं सांसद चंद्रशेखर साहू, पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, भाजपा विधायक मोतीलाल साहू, कांग्रेस विधायक संदीप साहू सहित समाज के कई वरिष्ठजन मौजूद रहे। बैठक में धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए समाज को जागरूक करने और धर्मांतरण रोकने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई।

साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र साहू ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि समाज के पदाधिकारी प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इसके लिए विशेष टीमें का गठन किया जाएगा, जो गांव-गांव और एक-एक परिवार तक पहुंचकर समाज के लोगों से संवाद करेंगी और जागरूकता फैलाएंगी। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य समाज को संगठित करना, लोगों से संवाद स्थापित करना और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए जल्द ही प्रदेशभर में चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में समाज की एकजुटता बनाए रखने, सामाजिक सरोकारों को मजबूत करने और विभिन्न मुद्दों पर सामूहिक रूप से कार्य करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समाज के पदाधिकारियों ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर भी समितियों के गठन का निर्णय लिया।

चलती ट्रेन में पत्थर मारकर फरार हुए आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल ने सीसीटीवी की मदद से धर दबोचा

- **12833 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस में हुई घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा, आरोपी पर रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई**

रायपुर। चलती ट्रेन में पत्थर मारकर यात्री को घायल करने वाले आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि शनिवार 27 जून को गाड़ी संख्या 12833 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री पर तुमसर रोड स्टेशन पर ट्रेन के प्रस्थान के बाद एक व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंका गया, जिससे यात्री घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मंडल सुरक्षा आयुक्त चेतन दिलीपराव जिचकारने जांच टीम का गठन कर घटना की जांच प्रारंभ करते हुए विभिन्न स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन विश्लेषण किया। जांच के दौरान नागपुर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हुई।

घायल यात्री द्वारा संदिग्ध की पहचान किए जाने के बाद उसकी तस्वीर गुप्त सूत्रों के माध्यम से सत्यापन हेतु भेजी गई। प्राप्त सूचना के आधार पर टीम ने संदिग्ध के निवास स्थान पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज एवं फोटो का मिलान किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम यश वल्द प्रकाश बर्वे (23 वर्ष), निवासी रविदास नगर, तुमसर, जिला भंडारा बताया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि यात्रा के दौरान दिव्यांग कोच में सीट को लेकर उसकी एक यात्री से कहासुनी हुई थी। इसी विवाद के कारण गंतव्य स्टेशन तुमसर रोड पहुंचने के बाद ट्रेन के चलने पर उसने गुस्से में यात्री पर पत्थर फेंका। आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे पूर्व में दर्ज रेल अधिनियम के अपराध में विधिवत गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।

सवा लाख का लैपटॉप ले भागा होटल में ठहरा फर्जी कस्टमर

रायपुर। होटल हयात में ठगी का नया मामला सामने आया है। एक ऐसा कस्टमर जो आलीशान कमरे में ठहरने आया था, वह चंद दिनों में ही होटल को दो लाख का चूना लगाकर गायब हो गया। होटल प्रबंधन ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, तमिलनाडु का रहने वाला भीमसेन जान 25 जून 2026 को रायपुर के होटल हयात में ठहरा था। उसे होटल के कमरा नंबर 512 में रुकने के लिए अलॉट किया गया था। शुरुआत में वह एक सामान्य मेहमान की तरह ही पेश आया। उसने होटल प्रबंधन से अपने जरूरी काम का हवाला देते हुए एक लैपटॉप की मांग की। मेहमान की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए होटल प्रबंधन ने भी बिना किसी संदेह के बाहरी एजेंसी से एक महंगा लैपटॉप किराये पर मंगवाया और उसे उपलब्ध करा दिया। आरोपित ने 27 जून की सुबह बिना किसी को खबर किए होटल से गायब हो गया। न तो उसने होटल के रिसेप्शन पर चेकआउट की सामान्य प्रक्रिया पूरी की और न ही अपने ठहरने का बकाया बिल चुकाया। जब होटल कर्मचारियों ने उसके कमरे की तलाशी ली, तो कमरा खाली मिला और मेहमान का कहीं पता नहीं था। जांच में सामने आया कि उस पर होटल का 63,755 रुपये का बिल बकाया था। वहीं, होटल द्वारा उसे उपलब्ध कराया गया लैपटॉप भी गायब था।

सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मोदी के नाम

सनत जैन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। इसके साथ ही पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए, जिन्हें अभी तक 34 देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा और इस सम्मान को लेकर विवादों का पिटारा भी भारत में खुलता हुआ नजर आ रहा है। सेशेल्स टैक्स हेवन देश है। इस देश की आबादी मात्र 1.1 लाख है। यह अफ्रीका का सबसे छोटा टापू है। इसका कुल क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमीटर है। इसकी गिनती समृद्ध देश के रूप में होती है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टैक्स हैवन देश के रूप में है। यह देश मत्स्य पालन, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं के लिए सारी दुनिया के देशों में पहचाना जाता है। यहां पर मुश्किल से 7 से 8000 भारतीय रहते हैं। इसमें से कुछ वर्षों में लगभग 2000 भारतीयों ने यहां की नागरिकता ली है। शेष भारतीय यहां पर जन्मजात रह रहे हैं। पनामा पेपर लीक में भी इस देश का नाम आया था। उस समय भी इसमें भारतीय नागरिकों के नाम थे। जिन्होंने अपना काला धन वहां जमा किया था। 2014 में जब केंद्र की सरकार बदली, उसके बाद यह माना जा रहा था, सरकार काला धन वापस लाने के लिए विशेष प्रयास करेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कालाधन बड़ा चुनावी मुद्दा था। इस समय नरेन्द्र मोदी ने विदेशों में जमा कालाधन वापिस लाने का वायदा किया था। विगत वर्षों में जिस तरह से टैक्स हेवन देशों का पैसा भारत के शेयर बाजार एवं कारोबार में निवेश किया गया है, उसको लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। इतने छोटे से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, लगभग तीन दिन तक रुकना, भारत में चर्चा का विषय बन गया है। भारत सरकार का कहना है, सेशेल्स हिंद महासागर का हिस्सा है। समुद्र का एक छोटा द्वीप होते हुए भी भारत के लिए सामरिक और समुद्री व्यापार के लिए उसका बड़ा महत्व है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से सेशल्स को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रही है। पनामा पेपर लीक मामले तथा शेयर बाजार में निवेश को लेकर कई आरोप सामने आ चुके हैं। भारत सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। भारत में मोदी सरकार के लिए कई चुनौतियां सामने हैं। अयोध्या के राम मंदिर दान एवं चढ़ावे का मामला इस समय चरम पर है। कुछ ही दिनों बाद मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन शुरू हो गए हैं। विपक्ष बहुत आक्रामक है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स जाना विवादों में आ गया है। उन्हें जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक और पहली बार नया सम्मान दिए जाने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। एक छोटे से टैक्स हेवन देश की यह यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आगे चलकर कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न ना कर दे, इसको लेकर तरह-तरह की आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम करें, उन्हें किसी भी स्तर पर कोई नुकसान हो, यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों की संख्या कम नहीं है। इस तरह के विरोध होते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के विरोध पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। सेशेल्स यात्रा को लेकर जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह के नुकसान के रूप में होगा, यह संभव ही नहीं है।

नागरिकता के दस्तावेजों पर इतना भ्रम ठीक नहीं

उमेश चतुर्वेदी

पिछले कुछ वर्षों में पासपोर्ट हासिल करना आसान हो गया है। इसकी वजह तकनीकी क्रांति तो है ही, लेकिन सरकारी नीतियों ने भी आम आदमी के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया है। पासपोर्ट हासिल करने के कठिन दौर से लेकर आसानी से प्राप्त होने के मौजूदा दौर में, आम नागरिक इसे अपनी नागरिकता का एक वैध दस्तावेज मानता रहा है। लेकिन पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के पासपोर्ट को लेकर दिए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस अधिकारी के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं। जहां पासपोर्ट हासिल करने को चार धाम यात्रा जैसी उपलब्धि माना जाता रहा हो, जहां किसी व्यक्ति की पहचान के लिए मजबूत सरकारी दस्तावेज माना जाता रहा हो, वहां ऐसा बयान आएगा तो विवाद होगा ही। तो विवाद हो रहा है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट नागरिकता का वैध दस्तावेज नही है तो फिर कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता के लिए क्या सबूत पेश करे।

भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के शब्दों से गुजरें तो विदेश मंत्रालय के अधिकारी का कहना गलत भी नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मतदाता सूचियों के विशेष और गहन परीक्षण के दौरान जब घोषित कर दिया गया कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना उसकी नागरिकता के सबूत नहीं है और अब पासपोर्ट भी नहीं रहा, तो फिर भारतीय नागरिक क्या करे। जरूरत पड़ने पर वह कैसे साबित करे कि वह भारतीय नागरिक है। इस आधार पर तो देश के ज्यादातर लोग अपनी नागरिकता को तो साबित ही नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज के दौर की तमाम लड़ाइयों का बुनियादी और मजबूत आधार चूंकि नैरेटिव बन गया है तो यह भी साबित करने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है। इसके लपेटे में मोदी समर्थक ताकतें भी आएंगी, भारतीय जनता पार्टी पर तो खैर सवाल उठेगा ही। इस नैरेटिव को खड़ा होने से पहले ही जरूरी है कि नागरिकता के वैध दस्तावेज को लेकर जारी

भ्रम को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अन्यथा भ्रम का यह कुहासा जितना फैलेगा, वह आम नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति गुस्सा और क्षोभ भरेगा। इससे तनाव बढ़ाने वाली ताकतों को भी मौका मिलेगा।

पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जो कहा है, वह गलत भी नहीं है। अपने देश में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी किया जाता है। जबकि भारत में नागरिकता की व्याख्या और प्रमाणिकता के लिए भारतीय नागरिकता कानून 1955 है। पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 के मुताबिक, अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है। बस शर्त यह होगी कि सरकार को ऐसा लगे कि उसके लिए पासपोर्ट जारी करना व्यापक जनहित में जरूरी है। इस कानून से साफ है कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। बेशक भारतीय पासपोर्ट सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है, लेकिन यह पत्थर की लकीर जैसा नियम नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 भारत सरकार को छूट देती है कि व्यापक जनहित में वह भारतीय नागरिक ना होने के बावजूद किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी कर सकती है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भले ही विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन पासपोर्ट के जरिए नागरिकता प्रमाणित करने के तीन अभियुक्तों समेत चार लोगों के दावे को बांबे हाईकोर्ट 2013 में ही खारिज कर चुका है। उन्होंने अपनी नागरिकता के लिए पासपोर्ट पेश किया था। बांबे हाईकोर्ट ने दो सितंबर 2013 के अपने फैसले में साफ कर दिया था कि अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है तो पासपोर्ट को अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं पेश कर सकते। वैसे आधार कार्ड का कानून भी मानता है कि आधार कार्ड सिर्फ निवास और पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आधार कानून 2016 की धारा में साफ लिखा है कि आधार कार्ड से नागरिकता की बजाय सिर्फ निवास स्थान और पहचान प्रमाणित होता है। इसकी वजह यह है कि आधार कानून के तहत 182 दिनों तक भारत में लगातार रहने वाले व्यक्ति को सरकार चाहे तो आधार कार्ड जारी कर सकती है। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय भी इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर चुका है। इसी तरह पैन कार्ड के लिए भी व्यवस्था दी गई है। पैन कार्ड का कानूनी आधार है कि व्यक्ति अर्जन कर रहा है और टैक्स दे रहा है।

आधुनिक विश्व व्यवस्था की एक खामी यह है कि यहां कानून की भाषा अलग होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कानूनी भाषा जटिल होती है और उसके शब्द जाल को आम आदमी नहीं समझ पाता। इसी आधार पर उसकी अवधारणाएं विकसित होती हैं और फिर वह किसी विषय का व्यवस्था को लेकर अपनी राय बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी को इन जटिलताओं की समझ है, शायद यही वजह है कि उनके कार्यकाल में देश के सैकड़ों गैरजरूरी कानूनों को या तो रद्द किया गया है या फिर कुछ नए संदर्भों वाले कानूनों में समाहित कर दिया गया है। आज के दौर में नागरिकता के दस्तावेज के रूप जब पासपोर्ट, आधार कार्ड , पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को आखिरी और अंतिम प्रमाण मानने से इनकार किया जाता है तो अपनी लोक और आम धारणा के चलते आम आदमी इसके विरोध में उतर आता है। यही वजह है कि जब मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के दौरान इन दस्तावेजों को आखिरी दस्तावेज मानने से इनकार किया गया तो इसका विरोध शुरू हुआ था। कुछ इसी अंदाज में पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूछ लिया है कि पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस जब व्यक्ति का सत्यापन करती है तो आखिर वह किसका सत्यापन करती है और क्यों करती है? उनका यहां तक कहना है कि इससे लोगों के मन में यह भी संदेह उत्पन्न हो सकता है कि गैर भारतीयों को भी पासपोर्ट दिए जा रहे हैं?

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भारत सरकार की ओर से नगारकिता के प्रमाण को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब पासपोर्ट मान्य नहीं, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भरोसा नहीं और पैन कार्ड मान्य नहीं तो फिर आम नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे साबित करे। निश्चित तौर पर इसका भी सरकारी व्यवस्था में है। 20 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा था, %जन्म की तारीख और जन्म-स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।% इसमें रिलीज में कहा गया था कि जन्म की तारीख और जन्म स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, इन दस्तावेजों के बारे में आखिरी रूप से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसमें वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर से जुड़े दस्तावेज या सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ऐसे ही अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में और भी दस्तावेज़ शामिल किए जा सकते हैं ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को बेवजह परेशानी न हो।

बेशक कानून की भाषा अलग होती है और लोक का शब्द संसार अलग, लेकिन दोनों के बीच संतुलन होना ही चाहिए। लोक की समझ अपने तंत्र के लिए बेहतर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोक और कानून की भाषा के बीच के अंतर को पाट लिया जाए। अन्यथा गलतफहमियां होती रहेंगी और आखिरकार इससे नुकसान लोकतंत्र का होगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(कश्यपस्य) चराचर के द्रष्टा तेजोमय भगवान् के (ज्योतिषा वर्चसा च) अन्धकारविनाशक और हृदय प्रकाशक प्रकाश द्वारा [परिवेष्टित हुना मैं] (जरदष्टिः) रोगरहित दृढाङ्ग होते हुये अनेक भोगों को भोगता हुआ (कृतवीर्य्यः=[सायणीयपाठे] शतवीर्य्यः) अनेक कार की सामर्थ्य, किंवा सेंकड़ों सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति वाला (गिहायाः) सब तरह से अप्रतिरुद्धगति-सम्पन्न (एवं) (सुकृतः) पुण्य कर्म करता हुआ, अथवा भली प्रकार बना ठना (सहस्त्रायुः) अपरिमित आयु वाला होकर (चरेयम्) यथेच्छ विचरू।

(ख) आयु का प्रमाण सहस्त्र है।

(ग) जो भी सौ वर्ष तक या इससे भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है वही निश्चय से अमृतपन को प्राप्त होता है। (घ) पुरुष के जीवन की मर्यादा सो वर्ष है उसका पराक्रम और इन्द्रियें भी सौ वर्ष तक बनी रहती हैं। (ङ) निश्चित ही पुरुष सौ वर्ष से बहुत अधिक वर्षों तक जीवित रहता है (च) मैं सत्य द्वारा सुरक्षित, तथा वसन्तादि सत्र ऋतुवों से सुरक्षित एवं पूर्व उत्पन्न हुये पदार्थों से तथा भविष्य में पैदा होने वाली वस्तुओं से पालित हूं। नरक में डालने वाला कोई भी पाप मेरे पास न आये, तथा मौत भी मेरे निकट न फटके ! मैं इस अभिमन्त्रित जल से अपने आपको सब ओर से छुपाता हूं। (छ) मैं जीवों के लिए यह मर्यादा स्थापित करता हूं कि इन जीवों में से कोई भी इस (अर्थ) मृत्यु पथ को (नु) अवधि से पहिले प्राप्त न हो ! (पुरूचीः) सब तरह से जीवन व्यापार में सचेष्ट रहते हुये ये प्राणी सौ वर्ष पर्य्यन्त जीवित रहें ! मृत्यु को पर्वत (की कन्दरा) में बन्द किया जाए। (ज) सूर्य भगवान् हमें अमरपन में नियत करें, मृत्यु हम से दूर जाय और अमृत हमें प्राप्त हो । (झ) बुढ़ापे से पूर्व मत मरो ।

क्रमशः ...

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस

अनन्या मिश्रा

हर साल 01 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टरों के अथक प्रयासों, निस्वार्थ समर्पण और समाज के प्रति उनकी अमूल्य सेवाओं की सराहना के लिए मनाया जाता है। हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसलिए यह दिन न सिर्फ उनकी मेहनत को सराहता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की चुनौतियों और प्रगति पर चर्चा का भी अवसर प्रदान करता है।

साल 1991 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की शुरुआत की गई थी। इस दिन यानी की 01 जुलाई 1882 को प्रख्यात दूरदर्शी चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ बिधान चंद्र राय का जन्म हुआ था और 01 जुलाई 1962 को निधन हुआ था। डॉ बिधान चंद्र राय ने भारतीय चिकित्सा परिषद और कई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में अहम योगदान दिया था। इस कारण साल 1961 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसलिए उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाए जाने का फैसला लिया गया। भौगोलिकसंदर्भ

इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर्स हमेशा मरीजों के इलाज के लिए तटस्थ खड़े रहते हैं। यह दिन स्वास्थ्य सेवा में सुधार, मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने और डॉक्टरों की भलाई के लिए जागरुकता बढ़ाने का मौका है।

विश्व में अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। जैसे- एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इलेक्ट्रोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, हास्य योग, हास्य थिरेपी आदि चिकित्सक को मरीज से कभी यह नहीं कहना चाहिए कि आपकी बीमारी लाइलाज है वरन् यह कहना चाहिए कि आपका इलाज हमारी पैथी में नहीं है। जहां दवा कार्य नहीं करती वहां दुआ से भरी उम्मीद कार्य करती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि जो व्यक्ति उत्साहपूर्ण होगा, खुश होगा, सन्तुष्ट होगा, उसे सहसा किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह बीमार भी पड़े तो जल्द ही ठीक हो जाता है। हंसने पर हमारे शरीर में पेट के स्नायुओं में लयबद्ध हलचल पैदा होती है और अंतड़ियों में भी संतुलित घर्षण निर्माण होती है। इस कारण पाचनशक्ति में सुधार होता है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने 'हास्य' पर शोध किया है। उसके निष्कर्ष यही दिखाते हैं कि हास्य, स्मृति, मन के स्तर पर संतोष की खास लहरें निर्माण करती हैं। रासायनिक खेती, प्रदूषण तथा खाने-पीने की चीजों में मिलावट आदि भी अनेक रोगों के मुख्य कारण हैं।

डॉक्टरों की सराहना करने के लिए, यह समझना आवश्यक है कि उन्हें प्रतिदिन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक चिकित्सक ऐसे वातावरण में काम करते हैं जो चिकित्सा इतिहास में किसी भी समय की तुलना में कहीं अधिक सक्षम और चुनौतीपूर्ण है।

मरीजों की बढ़ती संख्या, दीर्घकालिक बीमारियों का बढ़ता बोझ और बढ़ती उम्र वाली आबादी ने भारत के स्वास्थ्य सेवा ढांचे पर अत्यधिक दबाव डाल दिया है।

क्या है अमेरिका-ईरान एमओयू का आर्टिकल-5?

अभिनय आकाश

अमेरिका और ईरान के बीच बारूद का धुआं अभी छंटा भी नहीं था कि दोनों देश एक नए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दुश्मनी की आग ठंडी करने के लिए जो समझौता हुआ था, अब वही समझौता दोनों के बीच नई जंग की वजह बन गया है। पिछले वीकेंड पर दोनों देशों ने एक-दूसरे पर इतने ताबड़तोड़ पलटवार किए कि महज़ 11 दिन पुराना शांति समझौता वेंटिलेटर पर आ गया था। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से कांप रही थी। लेकिन आखिरी कगार पर पहुंचकर दोनों ने अपनी सैन्य गतिविधियों को रोका और अब मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में दोनों महाशक्तियां फिर से मेज पर आमने-सामने बैठने जा रही हैं। इस आपातकालीन युद्धविराम ने दुनिया के सिर से महायुद्ध का तात्कालिक खतरा तो टाल दिया है, लेकिन सुलगता हुआ असली सवाल आज भी वहीं खड़ा है। समुद्र के सबसे बड़े सुल्तान का ताज किसके सिर सजेगा?

समझौता ज्ञापन का आर्टिकल 5 ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण महीनों से बाधित समुद्री व्यापार को फिर से शुरू करने पर केंद्रित है। इस क्लॉज (धारा) के तहत ईरान के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की सुविधा दे और उन सभी सैन्य व तकनीकी बाधाओं को हटाए जो सामान्य शिपिंग को रोक रही हैं। ईरान केवल 60 दिनों के लिए फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी और इसके विपरीत (आने-जाने वाले) वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए बिना किसी शुल्क के अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करके व्यवस्था करेगा। इस समझौते के तहत तेहरान को 30 दिनों के भीतर सैन्य बाधाओं को हटाने, बारूदी सुरंगों को साफ करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून व तटीय राज्यों के अधिकारों के अनुरूप हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भविष्य के प्रबंधन को तय करने के लिए ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मिलकर काम करने

की आवश्यकता है। हालांकि दोनों पक्ष जलमार्ग को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस संक्रमण काल के दौरान शिपिंग को कैसे संभाला जाए, इसे लेकर दोनों अलग-अलग निष्कर्षों पर पहुंचे हैं।

भले ही अंतरिम समझौते में वाणिज्यिक यातायात को फिर से शुरू करने की बात कही गई है, लेकिन ईरान का कहना है कि इस जलडमरूमध्य से होने वाला नेविगेशन (आवाजाही) अभी भी उसके अधिकार क्षेत्र में है। रविवार को बगदाद की यात्रा के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि समझौता स्पष्ट रूप से तेहरान की भूमिका को स्वीकार करता है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य अगले 30 दिनों तक ईरान की पूरी निगरानी और प्रबंधन में रहेगा, और सभी बाधाएं हटने के बाद, इस जलमार्ग की पूरी क्षमता बहाल कर दी जाएगी। हम इसी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि यह जिम्मेदारी पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की है। इस मामले में कोई दूसरा पक्ष या देश शामिल नहीं है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत यह पूरी तरह से स्पष्ट है, और किसी भी तरह का हस्तक्षेप या एकतरफा कार्रवाई स्थिति को और खराब करेगी और जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में देरी का कारण बनेगी।

ताज़ा संकट तब शुरू हुआ जब होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हमले हुए। शुक्रवार को सिंगापुर के झंडे वाले एवर लवली जहाज़ पर एक ड्रोन से हमला हुआ, जबकि एक दिन बाद पनामा के झंडे वाले किकू जहाज़ पर हमला किया गया। ईरान ने इनमें से किसी भी घटना की ज़िम्मेदारी नहीं ली। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं, तटीय रडार ठिकानों और अन्य सैन्य बुनियादी ढांचों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले कमर्शियल शिपिंग के ख़िलाफ़ ईरान की लगातार आक्रामकता के सीधे जवाब में किए गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि ईरान ने युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हो सकता है कि एक समय ऐसा आए जब हम और ज़्यादा समझदारी से काम न ले पाएँ, और हमें उस काम को सैन्य तरीक़े से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिकी हमले अंतरराष्ट्रीय क़ानून और खुद उस मेमोरेंडम (समझौते), दोनों का उल्लंघन थे। बाद में, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी मिसाइलें और ड्रोन दागे।

हालिया टकराव ने आर्टिकल 5 की अलग-अलग व्याख्याओं को साफ तौर पर उजागर किया है। वॉशिंगटन का कहना है कि समझौता बिना किसी रोक-टोक के कमर्शियल नेविगेशन की गारंटी देता है और उसने ओमान तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अधिकारियों से जुड़े वैकल्पिक शिपिंग इंतज़ामों का समर्थन किया है। हालांकि, ईरान इस बात से सहमत है कि शिपिंग फिर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन सभी जहाजों को तेहरान के साथ तालमेल बनाए रखना होगा क्योंकि समझौते को लागू करने की अवधि के दौरान यह जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) ईरानी प्रशासन के नियंत्रण में है। पिछले हफ़्ते यह विवाद तब और गहरा गया जब आईआरजीसी ने जहाजों को ईरानी समुद्री सीमा के भीतर केवल उत्तरी शिपिंग कॉरिडोर का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। समुद्री निगरानी फर्म विंडवर्ड एआई के अनुसार, ओमान के समुद्री क्षेत्र से दक्षिणी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे चार टैंकरों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि कई अन्य जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। इसके बाद इस जलडमरूमध्य से होने वाली शिपिंग में कमी आई। बुधवार को जहां रोज़ाना 70 जहाज गुज़रते थे, वहीं शनिवार तक यह संख्या घटकर सिर्फ़ 40 रह गई।

मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिनेवा में शुरुआती बातचीत के बाद अब अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने-सामने बैठने जा रहे हैं। इस बार बातचीत का मंच होगा क़तर की राजधानी दोहा जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि होर्मज स्ट्रेट को लेकर चल रहे सबसे बड़े विवाद का समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। यह वही होर्मज स्ट्रेट है जहां से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का कच्चा तेल समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसलिए यहां पैदा होने वाला कोई भी संकट केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और समुद्री व्यापार को प्रभावित करता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को होने वाली इस बैठक का मुख्य उद्देश्यहाल के दिनों में पैदा हुए तनाव को कम करना और अंतरराष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कारवाही रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर सहमति जताई है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ना अमेरिका कोई नया हमला करना चाहता है और ना ही ईरान स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ना चाहता है। हालांकि यह समझौता अभी बेहद नाजुक दौर में है। युद्ध विराम लागू हुए अभी केवल 11 दिन ही हुए हैं और दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

आज का इतिहास

1866 रोमानिया का पहला संविधान शुरू किया गया।
1867 कनाडा के प्रांत, न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोटिया को कनाडाई परिसंघ में एकजुट करके ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम लागू हुआ।
1874 रेमिंगटन नंबर 1 बिक्री पर चला गया, यह पहला व्यावसायिक रूप से सफल टाइपराइटर बन गया।
1875 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गयी।
1879 अमेरिकन इंजीलवादी चार्ल्स टेज़ रसेल ने द वॉचटावर का पहला प्रकाशन प्रकाशित किया, जो कि द वर्ल्ड में सबसे अधिक प्रसारित पत्रिका है।
1881 दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल सेंट स्टीफन, न्यू ब्रंसविक, कनाडा और कैलिस, मेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच किया गया था।
1881 फोन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय बातचीत कलैस और में-सेंट स्टीफंस के बीच हुई।
1887 एफिल टॉवर के लोहे के ढांचे के निर्माण पेरिस फ्रांस में शुरू किया गया।
1889 फ्रेडरिक डगलस हैती के लिए मंत्री नामित बने।
1893 अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड गुप्त रूप से पर संचालित किया गया।
1896 अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन कांग्रेस लंदन में खोला गया।
1907 ऑरेंज रिवर कॉलोनी ने ऑरेंज फ्री स्टेट के रूप में स्वायत्तता हासिल की।
1911 जर्मन गनबोट पैंथर जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और फ्राँस के बीच अगाडिर संकट को भड़काने वाले अगाडिर के मोरक्कन बंदरगाह में पहुँचा।
1915 प्रथम विश्व युद्ध के जर्मन फाइटर पायलट कर्ट विंटेन्स, अतुल्यकालिक मशीनगन का उपयोग करके हवाई युद्ध में एक और विमान को मार गिराने वाले पहले व्यक्ति बन गए।
1916 प्रथम विश्व युद्ध-सोम्मे की लड़ाई का पहला चरण, अल्बर्ट की लड़ाई का पहला दिन, ब्रिटिश सेना के इतिहास में सबसे खून का दिन बन गया, जिसमें 57,470 लोग हताहत हुए, जिनमें से 19,240 लोग मारे गए या घाव से मारे गए।
1921 कोयला हड़ताल इंग्लैंड में समाप्त हो गई।
1927 कनाडा में पहली तट-से-तट रेडियो नेटवर्क जोड़ने का काम डोमिनियन की 60 वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए किया गया।
1932 ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रसारक, ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम, का गठन किया गया था

चीन देखता रह गया, हिंद महासागर में भारत ने बना ली मजबूत घेराबंदी

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में केवल एक सहभागी शक्ति नहीं, बल्कि स्थिरता, सुरक्षा और विकास का सबसे भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। सेशेल्स की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई यह यात्रा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की संसद को संबोधित करते हुए जिस प्रकार हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाने की बात कही, वह भारत की दूरदर्शी समुद्री नीति का स्पष्ट संकेत है। भारत ने यह संदेश दिया कि हिंद महासागर केवल समुद्री व्यापार का मार्ग नहीं, बल्कि सामरिक संतुलन, आर्थिक समृद्धि और वैश्विक शक्ति संरचना का केंद्र बनने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में मोदी सरकार की विदेश नीति का आत्मविश्वास और परिपक्वता साफ दिखाई दी। सेशेल्स को भारत ने जिस सम्मान और साझेदारी का भरोसा दिया, उसने यह साबित किया कि नई दिल्ली छोटे देशों को भी बराबरी और सम्मान के साथ साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है।

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नौ महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें प्रत्यर्पण संधि सबसे अधिक सामरिक महत्व रखती है। हिंद महासागर क्षेत्र लंबे समय से समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अंतरराष्ट्रीय अपराधों की चुनौती से जूझता रहा है। ऐसे में प्रत्यर्पण समझौता और समुद्री सुरक्षा सहयोग भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करने वाला कदम है। इससे भारत को पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और निगरानी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत और सेशेल्स की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भारत ने सेशेल्स को तेज गश्ती पोत, नौकाएं, एंबुलेंस और अन्य उपयोगी वाहन भेंट किए। भारतीय नौसेना के युद्धपोत और सर्वेक्षण पोत का सेशेल्स पहुंचना हिंद महासागर में भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रदर्शन भी था।

साथ ही भारत ने सेशेल्स के लिए एक सौ पचहत्तर मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर यह भी दिखाया कि उसकी विदेश नीति केवल रणनीतिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास आधारित साझेदारी पर आधारित है। सामाजिक आवास, शिक्षा, परिवहन, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारत का सहयोग यह दर्शाता है कि नई दिल्ली अपने साझेदार देशों के विकास को अपनी प्राथमिकता मानती है। मोदी सरकार की यही नीति भारत को अन्य वैश्विक शक्तियों से अलग पहचान देती है।

इस यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल और आर्थिक सहयोग भी रहा। भारत और सेशेल्स के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार, प्रत्यक्ष नौवहन संपर्क और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर हुए समझौते भविष्य की आर्थिक संरचना को बदलने वाले कदम हैं। भारत की डिजिटल सार्वजनिक संरचना को सेशेल्स में लागू करने की पहल यह साबित करती है कि भारत अब तकनीकी समाधान देने वाली वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है। यह मोदी सरकार की उस नीति का परिणाम है जिसमें तकनीक को जनकल्याण और वैश्विक साझेदारी का आधार बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन और छोटे द्वीपीय देशों की चुनौतियों को जिस मजबूती से उठाया, वह भी भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि जिन देशों ने जलवायु संकट पैदा नहीं किया, उन्हें उसका सबसे बड़ा बोझ नहीं उठाना चाहिए। यह बयान विकसित देशों की दोहरी नीतियों पर सीधा प्रहार भी था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी आधारभूत ढांचा गठबंधन और हरित ऊर्जा अभियानों के माध्यम से पहले ही विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बना ली है। सेशेल्स द्वारा भारत की पहल में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देशों के बीच भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स द्वारा दिया गया ब्लू होराइजन के संरक्षक सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह सम्मान पहली बार किसी नेता को दिया गया और इससे यह संदेश गया कि हिंद महासागर क्षेत्र भारत को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखता है। पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और समुद्री संसाधनों के संतुलित उपयोग को लेकर भारत की प्रतिबद्धता ने छोटे द्वीपीय देशों में विश्वास पैदा किया है।

सामरिक दृष्टि से देखें तो यह यात्रा चीन की बढ़ती समुद्री सक्रियता के बीच भारत की मजबूत जवाबी रणनीति का हिस्सा भी है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार बंदरगाह, आधारभूत ढांचे और कर्ज आधारित परियोजनाओं के जरिए प्रभाव बढ़ाने में लगा है। इसके मुकाबले भारत ने सहयोग, विश्वास और साझा विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि सेशेल्स जैसे देश भारत को केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि दीर्घकालिक साझेदार मानते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति ने पिछले एक दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को अभूतपूर्व मजबूती दी है।

साथ ही सेशेल्स की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर भारतीय सेना और नौसेना की ऐतिहासिक भागीदारी ने इसे भारत की सामरिक शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव के प्रदर्शन में बदल दिया। असम रेजिमेंट के जवानों, भारतीय नौसेना के बैंड और युद्धपोतों की मौजूदगी ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सुरक्षा का सबसे विश्वसनीय स्तंभ है। राजधानी विक्टोरिया में जब भारतीय सैनिकों ने कदमताल की और असम रेजिमेंट का प्रसिद्ध युद्धगान गूंजा, तब वह केवल सैन्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत और सेशेल्स के बीच दशकों पुराने भरोसे और रक्षा सहयोग का जीवंत प्रतीक था। युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षाक की उपस्थिति ने हिंद महासागर में भारत की समुद्री क्षमता और रणनीतिक पहुंच को और अधिक प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। यह संदेश भी साफ था कि मोदी सरकार हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य और सामरिक उपस्थिति को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बहरहाल, कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा स्पष्ट संकेत देती है कि आने वाले समय में हिंद महासागर की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका निर्णायक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स यात्रा ने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार की विदेश नीति दूरदर्शी, संतुलित और रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती उपस्थिति केवल सामरिक शक्ति का विस्तार नहीं, बल्कि विश्वास, विकास और साझी समृद्धि की नई कहानी है।

कराची में आतंकी हमला पाक की आंतरिक सुरक्षा विफलता

पवन

करावी के एक सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हुए आतंकी हमले में भारत की कथित संलिप्तता के पाकिस्तान के आरोपों को भारत सरकार द्वारा स्पष्ट व कड़े शब्दों में खारिज किया जाना सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह उस पुरानी प्रवृत्ति का मुंहतोड़ जवाब भी है, जिसके तहत इस्लामाबाद आंतरिक सुरक्षा में अपनी हर विफलता के बाद बगैर किसी साक्ष्य के भारत को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहा है।

हालिया घटना कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके की है, जहां आतंकियों ने सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स की मौत हो गई। इस गंभीर आंतरिक विफलता की समीक्षा करने के बजाय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी समेत पूरे तंत्र ने इस हमले के पीछे भारत का हाथ होने का झूठा राग अलापना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सेना यह स्वीकार कर चुकी है कि इस वारदात के पीछे प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के धड़े 'जमात-उल-अहरार' के आतंकियों का हाथ है।

दरअसल, आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान के लिए यह कोई नया रवैया नहीं है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान में जब भी हिंसा या उग्रवाद बढ़ता है, तो वह इसका आरोप भारत पर मढ़ देता है। वह भूल जाता है कि वैश्विक आतंकी ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादियों को पालने-पोसने वाली धरती उसकी अपनी ही रही है।

भारत तो दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। वर्ष 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से लेकर 2001 में संसद पर हमला, 2008 का मुंबई आतंकी हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला, उरी में सैन्य शिविर पर हमला और 2019 का पुलवामा हमला-इन सभी घटनाओं ने बार-बार पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क की भूमिका की ओर ही इशारा किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने भी आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग न रोक पाने के लिए पाकिस्तान को कई वर्षों तक 'ग्रे लिस्ट' में रखा था।

इसके बावजूद, अगर पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है, तो यह न केवल हास्यास्पद है, बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर उसके दोहरे रवैये का भी परिचायक है। पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उन आतंकी विचारधाराओं और संगठनों से है, जिन्होंने उसकी अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय साख को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। यदि वह इस चुनौती का ईमानदारी से सामना करता है, तो इसका लाभ न सिर्फ उसे, बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा।

शिवसेना में विभाजन: रणनीतिक निर्णय तय करेंगे भविष्य

कल्याणी शंकर

पिछले सप्ताह, 19 जून को, शिवसेना ने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। अपनी स्थापना के बाद से, पिछले 60 वर्षों में, पार्टी ने कई विभाजन देखे हैं, जिनमें से नवीनतम 26 जून को हुआ। शिव सेना की 60वीं वर्षगांठ को 2 गुटों-ठाकरे की सेना (यू.बी.टी.) और एकनाथ शिंदे की सेना द्वारा विवादित माना जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक पार्टी की मूल वैचारिक विरासत का दावा कर रहा है।

26 जून को, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यू.बी.टी.) के भीतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दरार तब उभरी, जब उसके 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ शिवसेना गुट में शामिल होने के लिए पाला बदल लिया। इससे लोकसभा में उनकी संख्या केवल 3 रह गई और शिंदे गुट की संसदीय ताकत मजबूत हो गई है। अपने 60 वर्षों में, शिवसेना 5 बार विभाजित हो चुकी है, जो आंतरिक विभाजनों के प्रति इसकी भेद्यता और इस तरह के संघर्षों के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है। 2003 में पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे द्वारा अपने बेटे उद्धव को सेना का कार्यकारी अध्यक्ष नामित करने से ठीक पहले, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके लिए एक प्रमुख संगठनात्मक भूमिका की मांग शुरू कर दी थी। बाद में, उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे की सेना में पदोन्नति ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया, जहां पार्टी नेताओं ने उन्हें युवा सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले 'अगली पीढ़ी' के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया।

28 नवंबर, 2019 को, शिवसेना के नेता और महा विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 21 जून, 2022 को, विधानसभा में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे कई अन्य विधायकों के साथ लापता हो गए। इस 'बागी' समूह ने पहले सूरत और फिर गुवाहाटी का रुख किया, यह दावा करते हुए कि एम.वी.ए. गठबंधन शिवसेना की विचारधारा के विपरीत है और मुख्यमंत्री ठाकरे में विश्वास की कमी व्यक्त की। 2022 के विभाजन के बाद, 56 में से 40 शिवसेना विधायक शिंदे के साथ हो गए। लोकसभा में, 18 में से 13 सांसद शिंदे खेमे में शामिल हो गए, जिससे उद्धव के पास केवल 5 सांसद बचे। दोनों गुट बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत के सही उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, जिसमें उद्धव अपने रक्त संबंध पर जोर देते हैं और शिंदे का तर्क है कि वह पार्टी की वैचारिक नींव को बनाए रखते हैं।

शिवसेना यू.बी.टी. में नवीनतम विभाजन ठाकरे परिवार के भविष्य पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। यह कई तरह से सामने आ सकता है-बागी नेताओं के बीच ठाकरे के नेतृत्व से असंतोष के कारण असहमति बढ़ रही है। उनका मानना है कि उन्होंने उनके साथ पर्याप्त जुड़ाव नहीं रखा, विशेष रूप से समर्थन के अनुरोधों के बावजूद उनके निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा न करके। विभाजन के बाद की चुनौतियों से निपटने और उद्धव गुट के अस्तित्व और पुनरुत्थान को सुनिश्चित करने के लिए, कई रणनीतिक कार्यों पर विचार किया जा सकता है =

शिकायतों को हल करने और समर्थकों के बीच एकता और विश्वास को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है। यदि गुट विभाजन और बदलती जनभावनाओं को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो वे भविष्य में अपना प्रभाव खोने का जोखिम उठाते हैं। विश्वसनीय और संबंधित नेताओं का समर्थन आत्मविश्वास को प्रेरित, नए समर्थकों को आर्क़र्षित कर सकता है और मौजूदा आधार को ऊर्जावान बना सकता है। रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से समर्थकों को सशक्त बनाया और उनका समर्थन हासिल किया जा सकता है। स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने वाली आऊटरीच पहल और अभियान विश्वास और सांझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाना और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होना क्षेत्रीय पहचान और जनता के बीच सद्भावना को मजबूत कर सकता है। बदलती राजनीतिक भावनाओं और युवा पीढ़ी की अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होना प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस अवधि के दौरान आंतरिक सामंजस्य को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। आंतरिक संघर्षों को तेजी से हल करना और एक समावेशी वातावरण बनाना समर्थकों के बीच आशा और जिम्मेदारी की सांझी भावना को प्रेरित कर सकता है, जिससे पार्टी की एकता और लचीलापन मजबूत होगा।इन रणनीतियों को लागू करके, उद्धव गुट जीवित रह सकता है और महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से प्रभाव हासिल कर सकता है।

कोई भी गुट चुनावी रूप से आत्मनिर्भर नहीं है-शिंदे भाजपा की मशीनरी पर निर्भर है, जबकि उद्धव एम.वी.ए. के संयुक्त वोट शेयर पर। इसलिए, आगामी विधानसभा चुनाव इस बात की असली परीक्षा होगी कि शिवसेना का कौन-सा गुट जीवित रहता है। अंततः, परिणाम काफी हद तक उनके रणनीतिक निर्णयों और महाराष्ट्र के उभरते राजनीतिक परिदृश्य के प्रति प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। उनके द्वारा किए गए चुनाव ठाकरे परिवार और पार्टी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

सिलैक्टिव आक्रोश से कांग्रेस का इतिहास नहीं मिट सकता

आर.पी. सिंह

गाजा पर सोनिया गांधी का लेख नैतिकता का पाठ नहीं, बल्कि चयनात्मक आक्रोश का एक जीवंत उदाहरण है। भारत को मानवाधिकारों का उपदेश देने से पहले कांग्रेस नेतृत्व को स्वतंत्र भारत के सबसे काले अध्यायों में से एक, 1984 के सिख विरोधी नरसंहार और उसके बाद पंजाब में वर्षों तक चले दर्द और पीड़ा का जवाब देना चाहिए। नवम्बर 1984 में हजारों निर्दोष सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई। लोगों को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला गया, लोहे के सरियों से पीटा गया, उन पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। पूरे के पूरे परिवार समाप्त कर दिए गए। गुरुद्वारों का अपमान किया गया, घरों और दुकानों को लूटकर आग के हवाले कर दिया गया। बच्चों ने अपने पिता को भीड़ द्वारा मारते हुए देखा, माताओं ने अपने बेटों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। हजारों महिलाएं एक ही रात में विधवा हो गईं और अनेक जीवित बचे लोगों ने भयावह यौन ड्क्षहसा की ऐसी कहानियां सुनाईं, जिनके शारीरिक और मानसिक घाव आज तक नहीं भरे हैं।

गाजा के लिए आंसू बहाने से पहले सोनिया गांधी स्वयं से एक प्रश्न पूछें-क्या उन्होंने कभी सतनामी बाई के आंसू पोंछने की कोशिश की है? सतनामी बाई की गवाही 1984 के सिख विरोधी नरसंहार की सबसे हृदयविदारक गवाहियों में से एक है। 1 नवम्बर, 1984 को त्रिलोकपुरी में उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति मोहन सिंह, जो एक गरीब ऑटो-रिक्शा चालक थे, को लोहे के सरियों से पीट-पीटकर और जिंदा जलाकर मार डाले जाते देखा, जबकि उनकी गोद में उनकी नवजात बेटी थी। उस समय जब कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, उन्होंने और अनेक अन्य सिख महिलाओं ने बाद में भीड़ द्वारा किए गए भयावह यौन अत्याचारों का वर्णन किया। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।

क्या सोनिया गांधी ने कभी सार्वजनिक रूप से सतनामी बाई का नाम लिया? क्या वह कभी उनसे मिलीं, उन्हें गले लगाया या 1984 में सिख महिलाओं पर हुए अकल्पनीय अत्याचारों पर गहरा दुख व्यक्त किया? क्या उन्होंने कभी प्रत्येक पीड़ित को पूर्ण न्याय दिलाने की मांग की? दिल्ली में यह भयावहता समाप्त नहीं हुई। इसके बाद पंजाब वर्षों तक खून से लथपथ रहा। एक पूरी पीढ़ी आतंकवाद और आतंकवाद-रोधी अभियानों के बीच बड़ी हुई। हजारों परिवार अपने उन बेटों की तलाश करते रहे, जो कभी वापस नहीं लौटे। जबरन गायब किए जाने, अवैध अंतिम संस्कार, हिरासत में यातना और फर्जी मुठभेड़ों के आरोपों ने पंजाब के इतिहास पर गहरे घाव छोड़े। जत्थेदार गुरदेव सिंह कौंके की हिरासत में हत्या आज भी उस दौर के सबसे दर्दनाक प्रतीकों में से एक है।

भारत के सबसे राष्ट्रवादी और देशभक्त समुदायों में से एक, सिख समुदाय, जिसने देश की आजादी, एकता और सुरक्षा के लिए अतुलनीय बलिदान दिए, उसे आतंकवादियों की करतूतों के कारण संदेह की दृष्टि से देखा गया। जिस समुदाय ने भारत को अनगिनत शहीद दिए, उसी समुदाय को ऐसे बोझ का सामना करना पड़ा जिसका वह कभी दोषी नहीं था। सोनिया गांधी को अपने दिवंगत पति राजीव गांधी का वह बयान भी याद रखना चाहिए, जो उन्होंने 1984 की हिंसा के बाद दिया था-'जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।'

इस बयान की व्यापक रूप से आलोचना हुई क्योंकि इसे उस भीषण ड्क्षहसा को उचित ठहराने या उसकी गंभीरता को कम करके दिखाने के रूप में देखा गया। असंख्य सिख परिवारों के लिए यह बयान कांग्रेस की उस विफलता का प्रतीक बन गया, जिसमें उसने पीड़ितों के साथ बिना किसी शर्त के खड़े होने का नैतिक साहस नहीं दिखाया। नरसंहार के बाद भी कांग्रेस की राजनीतिक भाषा और उसके कुछ चुनावी विज्ञापन, जिन्हें अनेक सिखों ने समुदाय को राष्ट्रीय सुरक्षा और भय के चश्मे से देखने का प्रयास माना, ने घाव भरने की बजाय अलगाव की भावना को और गहरा किया। और आज वही सोनिया गांधी गाजा के मुद्दे पर नैतिकता का सर्वोच्च मंच ग्रहण करने का प्रयास कर रही हैं। हर निर्दोष नागरिक का जीवन चाहे वह फिलिस्तीनी हो, इसराईली, भारतीय या किसी भी अन्य देश का नागरिक, अनमोल है। भारत ने हमेशा मानवीय सहायता, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। लेकिन नैतिक विश्वसनीयता के लिए निरंतरता आवश्यक है।

भारत को मानवता का पाठ पढ़ाने से पहले सोनिया गांधी को यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली की सिख विधवाओं, 1984 के अनाथ बच्चों, दशकों तक न्याय की प्रतीक्षा करने वाले परिवारों और पंजाब के पीड़ितों के लिए कभी वही नैतिक संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई, जो आज गाजा के लिए प्रदर्शित कर रही हैं। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि यह लेख सार्वभौमिक मानवाधिकारों से अधिक भारत की घरेलू राजनीति से प्रेरित है। बहुत से लोग इसे भारत में मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने का प्रयास मानेंगे, जबकि कांग्रेस अब भी अपने इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों का पूरी ईमानदारी से सामना करने से बच रही है। इतिहास सिलैक्टिव नहीं हो सकता। मानवाधिकार सिलैक्टिव नहीं हो सकते। करुणा भी सिलैक्टिव नहीं हो सकती।

मर्यादा के मंदिर में पारदर्शिता की घंटी कब बजेगी?

सोनम लववंशी

राम भारतीय मानस में केवल एक नाम नहीं, बल्कि मर्यादा का पर्याय हैं। इसलिए जब उनके नाम से जुड़ी किसी संस्था, ट्रस्ट या व्यवस्था पर वित्तीय अनियमितताओं, कथित गबन या अपारदर्शिता के आरोपों की चर्चा होती है, तब चोट केवल कानून को नहीं लगती है। यह घाव समाज की आत्मा पर पड़ता है। ईंट-पत्थर से बने मंदिरों की मरम्मत संभव है, लेकिन टूटे हुए विश्वास का पुनर्निर्माण सबसे कठिन कार्य है। इतना ही नहीं विडंबना यह है कि इस देश में धर्म की रक्षा के नाम पर अक्सर धर्म के मूल तत्व सत्य, ईमानदारी और उत्तरदायित्व को ही सबसे पहले किनारे रख दिया जाता है। प्रश्न पूछने वाले को संदेह की निगाह से देखा जाता है, जबकि हिसाब देने वाले से कोई प्रश्न नहीं किया जाता। मानो श्रद्धा का अर्थ विवेक का परित्याग हो। यह वही समाज है जो दान-पात्र में नोट डालते समय आँखें बंद कर लेता है और बाद में खुलासों पर आँखें मलता रह जाता है। कबीर ने लिखा था कि, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उनका आशय भक्ति की उस अमूल्य संपदा से था जिसे हर कोई बिना मूल्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन समय ने इस पंक्ति का ऐसा विडंबनापूर्ण रूप गढ़ दिया है कि अब कई बार यह प्रश्न उठने लगता है। क्या कहीं राम साधना का नहीं, साधन का नाम बनते जा रहे हैं? क्या आस्था की छाया में जवाबदेही का सूर्य अस्त हो जाता है? ऐसे में यदि राम मंदिर या उससे जुड़े किसी ट्रस्ट के संदर्भ में वित्तीय गड़बड़ियों या कथित गबन की बातें सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनती हैं, तो सबसे पहली अपेक्षा निष्पक्ष जांच और पूर्ण पारदर्शिता की होनी चाहिए। जो संस्था स्वयं को नैतिक आदर्शों का प्रतिनिधि मानती है, उसे सामान्य संस्थाओं से कहीं अधिक कठोर सार्वजनिक परीक्षण स्वीकार करना चाहिए। यदि सब कुछ सही है तो जांच से प्रतिष्ठा बढ़ेगी; यदि नहीं, तो सुधार का मार्ग खुलेगा। दोनों ही स्थितियों में सत्य का लाभ होगा। सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि भगवान राम ने राजपाट त्यागकर मर्यादा बचाई थी, लेकिन आज कहीं-कहीं मर्यादा को त्यागकर प्रतिष्ठान बचाने की बेचैनी दिखाई देती है। राम ने न्याय के लिए अपने निजी सुखों का बलिदान दिया था, जबकि आधुनिक समय में कुछ लोग न्याय से बचने के लिए राम के नाम का सहारा खोजते दिखाई देते हैं। यह विरोधाभास केवल हास्यास्पद नहीं, गहरी नैतिक विफलता का संकेत है। समाज का एक हिस्सा हर आरोप को बिना जांच अंतिम सत्य मान लेता है और दूसरा हर आरोप को बिना जांच षड्यंत्र कहकर खारिज कर देता है। दोनों प्रवृत्तियाँ लोकतांत्रिक चेतना को कमजोर करती हैं। न अंधविश्वास स्वस्थ है, न अंध-अविश्वास। आवश्यकता तथ्यों, स्वतंत्र जांच और सार्वजनिक जवाबदेही की है। कानून और नैतिकता दोनों का सम्मान तभी संभव है जब भावनाएँ प्रमाणों का स्थान न ले लें। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार से भी अधिक चयनात्मक नैतिकता है। यदि आरोप किसी विरोधी पर हों तो हम न्याय की माँग करते हैं, और यदि वही प्रश्न अपने प्रिय पक्ष पर उठे तो उसे आस्था पर हमला घोषित कर देते हैं। सिद्धांतों का मूल्य तभी है जब वे व्यक्ति, दल, विचारधारा और संस्था से ऊपर खड़े रह सकें। अन्यथा नैतिकता केवल भाषणों की सजावट बनकर रह जाती है। राम का नाम किसी आर्थिक लेन-देन की ढाल नहीं बन सकता। वह तो स्वयं सत्य की कसौटी है। यदि किसी ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के विश्वास और दान का दुरुपयोग किया हो, तो वह केवल वित्तीय अपराध नहीं बल्कि नैतिक विश्वासघात भी होगा। और यदि आरोप असत्य हों, तो उन्हें तथ्यों और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से खारिज किया जाना चाहिए, न कि भावनात्मक नारों के सहारे। यह भी विचारणीय है कि मंदिर की भव्यता केवल शिखर की ऊँचाई से नहीं मापी जाती। उसकी वास्तविक ऊँचाई उसके लेखे-जोखे की ईमानदारी, प्रशासन की पारदर्शिता और प्रबंधन की जवाबदेही से तय होती है। संगमरमर की चमक उस समय फीकी पड़ जाती है जब हिसाब की किताब धुंधली दिखाई देने लगे। राम भारतीय संस्कृति में इसलिए पूजनीय नहीं हैं कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने शक्ति पर मर्यादा को वरीयता दी। यदि आज उनके नाम पर बनी किसी भी व्यवस्था में मर्यादा की जगह अपारदर्शिता, सत्य की जगह प्रचार और जवाबदेही की जगह मौन ले ले, तो सबसे बड़ा अपमान राम का नहीं होगा। सबसे बड़ा अपमान उन मूल्यों का होगा जिनके कारण राम युगों-युगों तक आदर्श बने रहे। समय की माँग स्पष्ट है= श्रद्धा बनी रहे, किंतु उसके साथ साहस भी जुड़ा रहे; मंदिर खड़े रहें, लेकिन उनके साथ सत्य भी खड़ा रहे; दान आता रहे और उसके साथ सार्वजनिक लेखा-परीक्षा भी चलती रहे। क्योंकि अंततः राम की सबसे बड़ी पूजा दीप जलाने में नहीं, सार्वजनिक जीवन को मर्यादा, ईमानदारी और सत्य के प्रकाश से आलोकित करने में है।

बॉस को खुश करना है? यह उपाय करिये फिर देखें चमत्कार

शाम को ऑफिस से लौटते वक्त आप सोचते होंगे कि दिन-रात मेहनत करता रहता हूँ लेकिन बॉस का ध्यान मुझ पर जाता ही नहीं। सुबह ऑफिस आते वक्त आप प्लानिंग करते होंगे कि आज मैं ऐसा करके या वैसा करके बॉस का दिल जीत लूंगा फिर मेरी तरक्की तय है। पर ऑफिस पहुंचते ही पिछले दिन का बचा काम निबटाते निबटाते इतना समय लग जाता होगा कि कुछ नया कर के दिखाने का समय ही नहीं मिलता होगा। कुछ नया कर दिखाने का समय मिलता भी होगा तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि काम आपने किया लेकिन श्रेय कोई और ले गया। इन सब वाकयों से किसी भी व्यक्ति का निराश होना स्वाभाविक ही है। आखिर इंसान का मन अपनी मेहनत का फल चाहता ही है, इंसान अपना अगला दिन पिछले दिन के मुकाबले बेहतर जीना चाहता ही है।

आइए यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिन पर अमल करके आप बॉस की नजरों में ही नहीं ऑफिस के पूरे स्टाफ की नजरों में भी चढ़ सकते हैं। और यकीन जानिये यदि ऐसा हो गया तो फिर आपकी तरक्की तय है-

समय का प्रबंधन जरूरी

सफलता के लिये यह बेहद जरूरी है कि आप समय को पैसे की तरह खर्च करना सीखें। समय की पाबंदी यदि जीवन में नहीं है तो व्यक्ति किसी भी सूरत में सफल नहीं हो सकता। आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसे समय पर ही नहीं समय से पहले ही पूरा करके देंगे तो अच्छा रहेगा। यदि प्रोजेक्ट में ऑफिस के किसी सहयोगी की मदद भी लेनी है तो उसे प्यार से समझाएं, यदि आप आदेश के जरिये काम लेंगे तो वह या तो मन से काम नहीं करेगा या फिर उसमें देर करवायेगा। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की औपचारिकता निभाने की जगह प्रोजेक्ट में कुछ रचनात्मकता दिखाएंगे तो यकीनन बॉस की नजरों में आप दूसरों से अलग साबित होंगे।

अपडेट रहना जरूरी

आप जिस क्षेत्र में भी नौकरी करते हों उस क्षेत्र की गतिविधियों और नई तकनीक से आपको खुद को अपडेट रखना चाहिए। यदि आप तकनीकी व्यक्ति न होते हुए भी तकनीकी रूप से कुशल हैं तो इससे आपकी योग्यता बढ़ती ही है। अपनी कंपनी को नयी तकनीक से अवगत कराते रहने से आपका कद बढ़ेगा।

चुगलखोरी से बचें

अकसर ऑफिस पॉलिटिक्स की चर्चाएं कार्यालयों में होती रहती हैं जोकि गॉसिप के लिए तो ठीक हैं लेकिन यह किसी भी कार्यालय का माहौल बिगाड़ती हैं। यदि आपने आज किसी की चुगली बॉस से की है तो वह भी समय आने पर आपकी चुगली कर सकता है और यदि वह समय आपकी तरक्की होने का हुआ तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।

ऑफिस में गप्पेबाजी से बचें

हालांकि निजी कंपनियों में यह कम ही देखने को मिलता है कि कर्मचारी आपस में गप्पेबाजी कर रहे हों लेकिन फिर भी यदि आपके ऑफिस में ऐसा माहौल है तो उस माहौल से खुद को दूर करें। घर की बात ऑफिस में सबके साथ शेयर नहीं करें क्योंकि आपके सामने भले कोई आपकी किसी समस्या से सहानुभूति दर्शाए लेकिन पीछे से वह उस समस्या के लिए आपका मजाक भी उड़ा सकता है।

सोशल मीडिया से बचें

वर्किंग ऑवर में ऑफिस के पीसी या लैपटॉप पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करें और ना ही मूवी आदि देखें। मोबाइल फोन पर भी व्हाटसएप पर चैट करते रहने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहने या फिर ऑनलाइन गेम खेलते रहने से आप कंपनी की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। आपको भले लगे कि आपको मोबाइल पर सोशल मीडिया का उपयोग करते किसी ने नहीं देखा है लेकिन हो सकता है कि कोई आपकी पोस्टस पर नजर रख रहा हो और उसमें पोस्टिंग टाइम से पता चल जायेगा कि आप ऑफिस का काम कर रहे थे या सोशल मीडिया पर थे।

पहनावा ठीक हो

ऑफिस में फॉर्मेल कपड़ों में ही जाएं तो ठीक रहेगा। कैजुअल कपड़े आकर्षक तो लगते हैं लेकिन वह कार्यालय की शोभा नहीं बढ़ाते। चुस्त कपड़ों को पहनने से बचें और ज्यादा डियो आदि लगा कर नहीं घूमें। इसके अलावा आप जहां भी बैठ कर कार्य करते हैं उस स्थान की साफ सफाई और साज सज्जा पर भी ध्यान दें ताकि लोगों की नजरें खुद ही उस ओर आकर्षित हों।

आपके विचार

हर व्यक्ति की अपनी अलग धार्मिक आस्था या राजनीतिक विचार होते हैं इसलिए उसे किसी पर थोपने या उस पर किसी से बहस में उलझने की बजाय अच्छा है कि आप अपने विचार अपने पास ही रखें। हमेशा सभी के साथ सकारात्मक संवाद करें और चर्चाओं के दौरान अपने नये आइडिया को शेयर कर लोगों को प्रभावित करें।

सहयोग करें

ऑफिस के अन्य कर्मचारियों के साथ सदैव सहयोगात्मक रवैया रखें। जूनियर को ज्यादा से ज्यादा सिखाएं और सीनियर का ज्यादा से ज्यादा कहना मानेंगे तो बड़ी जिम्मेदारियों के लिए आपको ही आगे किया जायेगा। ऑफिस के लोगों से उधार आदि मांग कर अपनी छवि नहीं खराब करें। यदि आपको पैसे की जरूरत है तो कंपनी से एडवांस आदि की मांग करें।

ऑफिस में घर नहीं

घरवालों या रिश्तेदारों या फिर दोस्तों को अकसर ऑफिस में नहीं बुलाया करें क्योंकि इससे एक तो आपका कार्यसमय बर्बाद होता है तथा दूसरे लोगों का भी ध्यान भंग होता है।

संपर्कों का इस्तेमाल

अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर अपनी कंपनी को लाभ पहुँचाएं और जिस कार्य के लिए आपकी नियुक्ति की गयी है उस कार्य को तो निपुणता के साथ करें ही साथ ही अन्य कार्य भी करेंगे तो कंपनी आप पर और निर्भर होती जायेगी और आपको खुश करना चाहेगी। और आखिर में, यही कहा जा सकता है कि बॉस सब जानते हैं लेकिन तब तक कुछ नहीं करते जब तक वह मजबूर न हो जाएं इसलिए उक्त सुझावों पर आप गौर करें और इन्हें आजमाएं फिर देखें आपके बॉस भी आप पर विशेष कृपा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

पुरानी जींस से बनाएं क्रिएटीव चीजें

घर की सफाई करते समय घर में कई पुरानी चाजें मिलती हैं। जिसे लोग बाहर फैंक देते हैं। इसे फैंकने की बजाएं इसका इस्तेमाल घर की कई क्रिएटिव चीजें बनाने में कर सकते हैं जैसे- कुशन कवर,बैग और फुटवियर। आइए जाने कैसे करें इस्तेमाल।

1. कुशन कवर बनाएं

अगर आपके पास कोई पुरानी जींस है तो उससे आप कुशन कवर बना सकते हैं। इससे घर को अट्रेक्टिव लुक मिलेगा।

2. बैग बनाएं

मार्केट से कई जींस बैग खरीदें होंगे लेकिन अपनी पुरानी जींस से इसे घर पर ही बना सकते हैं। इस पर किसी पुराने बैग के हैंडल भी लगा सकते हैं।

3. बेड कवर

अगर आप अपने बेडरुम को कोई अट्रेक्टिव लुक देना चाहते हैं तो इसे अगल-अगल कलर की पुरानी जींस को जोड़ कर बनाएं।

4. होम डैकर

पेन स्टैंड, डोर मैट, टेबल मैट, फ्लोर कुशन्स और चेयर कवर बनाने के लिए जींस को इनकी शेप के हिसाब से काटे और स्टिच कर लें।

5. फुटवेयर सजाएं

आप फ्लिप-फ्लॉप, चप्पल्स और कैनवस को पुरानी जींस के कपड़े से न्यू लुक दे सकते हैं। जींस की पतली स्ट्रैप को काटकर उसे फिल्प-फ्लॉप और चप्पल के ऊपर लगाएं।

मौज मस्ती के फायदे

मौज-मस्ती करना किसको पंसद नहीं होता है, उस पर अगर ये आपके सेहत को लाभ पहुचाएं तो ये सोने पर सुहागा जैसा हो जाता है। जी हां, मौज मस्ती करना आपकी सेहत के लिए लाभदायक होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में मौज मस्ती करने पल वैसे ही कम होते है। लेकिन जब आप इस मूड में रहते तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को आराम देता है। ये आपके शरीर के खुश रहने वाले रसायनों की क्रिया को बढ़ाते है।

खुशी वाले रसायन

ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे पॉजीटिव हार्मोन हमारे शरीर को खुशी का अहसास दिलाते है। मौज मस्ती जैसी गतिविधियों से इनके उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती है। ये तनाव व अवसाद आदि से भी बचाव करती है, साथ ही दिमाग को भी सक्रिय करते है। अपने परिवार, दोस्त व पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।

नर्व सेल्स एक्टिव

आप जिन लोगो के साथ मौज मस्ती करते है तो पक्का ही आप को उनका साथ अच्छा लगता है। ये खुशी आपके लिए सेहतमंद होती है। इससे आपके दिमाग की 100 मिलियन नर्व सेल्स एक्टिव होती हैं। दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के एक दूसरे से कनेक्ट होने पर आप तनाव मुक्त और आराम महसूस करते हैं।

सफेद पदार्थ बढ़ाने में सहायक

सफेद पदार्थ दिमाग की गहरी परतों में पाया जाता है। ये न्यूरॉन्स के साथ मिलकर दिमाग में नर्व सिग्नल्स के प्रसारण को बेहतर करता है। यानि इसके बढ़ने से आप ज्यादा एक्टिव और स्मार्ट नजर आ सकते हैं। आप जब कुछ नई गतिविधि में शामिल होते हैं, तो आपके सारे सेंस एक्टिव होते हैं।

स्वस्थ रखने में सहायक

हर समय कुछ नया करते रहने से दिमाग क्रियाशील रहता है। जिससे अवसाद होने का खतरा कम रहता है। शारीरिक और मानसिक एक्टिविटी की कमी के कारण एक उम्र में आपकी नर्व सेल्स सफेद पदार्थ से जुड़ने से रुक सकती है। अगर आपके दिमाग में सफेद पदार्थ बढ़ता है, तो इससे बुढ़ापें में आप अल्जाइमर और मानसिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं।

ट्रैवलिंग के वक्त यूं पैक करें अपनी जूलरी

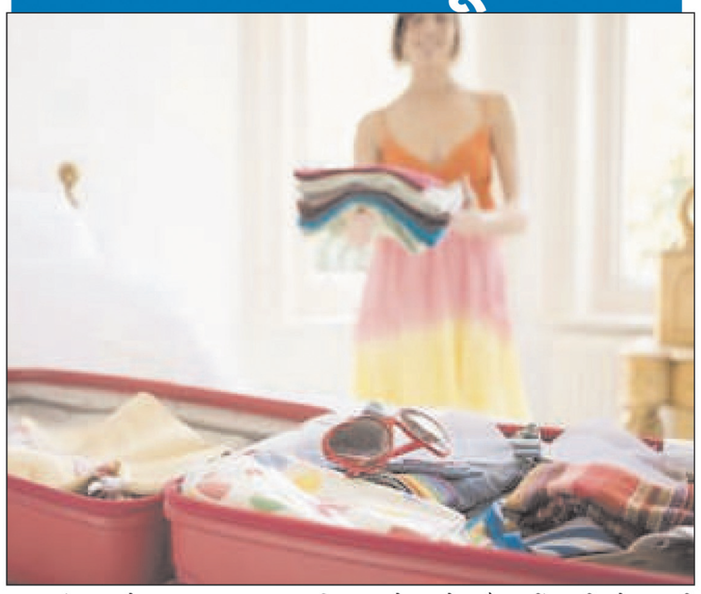

जहां एक ओर यात्रा करना, घूमना-फिरना मजेदार होता है। वहीं दूसरी ओर जूलरी की पैकिंग करना बोझिल मालूम पड़ सकता है। ऐसे में जूलरी ब्रैंड एनटाइस की क्रिएटिव डायरेक्टर मंजू कोठारी और मिनावाला के क्रिएटिव डायरेक्टर शहजाद जावेरी ने ट्रैवलिंग के दौरान जूलरी की सुरक्षित पैकिंग के संबंध में कई सुझाव दिए हैं।

» प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पाउच ईयर रिंग्स रखने के काम में आ सकते हैं। प्लास्टिक पाउच में लपेटकर उन्हें यात्रा के दौरान आसानी से ले जाया जा सकता है।

» छोटे ईयर रिंग्स को बटन में हैंग किया जा सकता है और फिर इन्हें छोटे बॉक्स या पाउच में रख लें।

» गले के हार या चेन को टूटने या मुड़ने से बचाने के लिए आप इन्हें स्ट्रॉ के बीच में रख सकती हैं, इससे ये सुरक्षित रहेंगे।

» आप चाहें तो मुलायम बेबी टॉवेल में भी सुरक्षित रूप से जूलरी को लपेटकर रख सकती हैं और तौलिए के आखिरी सिरे को बालों के बैंड से बांध लें।

» छोटी जूलरी जैसे ईयर रिंग और पेंडेंट को रखने के लिए आप टिन कंटेनर के बीच में कॉटन बॉल्स रखकर उसके ऊपर इन आभूषणों को रख सकती हैं, इससे ये सुरक्षित रहेंगे।

» आप मोजे में भी आभूषण पैक कर ट्रैवेल बैग में रख सकती हैं।

वजन के हिसाब से पीएंगे पानी तो हमेशा रहेंगे हैल्दी!

पानी पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि नियमित रूप से 2 लीटर पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सही मात्रा में पानी पीने से मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। कुछ लोग यह जान नहीं पाते कि उनके लिए कितना पानी पीना है। जरूरत से कम पानी पाने से विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और ज्यादा पानी पीने से जरूरी पोषक तत्वों पर भी बुरा असर पड़ता है।

वजन के हिसाब से पीए पानी

यह जरूरी नहीं कि हर किसी को दिन में 2 लीटर पानी ही पीना चाहिए। पानी की मात्रा आपके वजन पर निर्भर करती है। इसके लिए जरूरी है कि पहले अपने वजन की पुष्टि कर लें। 50 किलों और 70 किलो वाले वजन के लोगों कि पानी पाने की जरूरत अलग-अलग होती है।

इस तरह पीएं पानी

अपने सही वजन को 30 के साथ विभाजन करें। जैसे 60/30 = 2 यह पानी पीने की सही मात्रा है। 60 किलों वाले व्यक्ति को 2 लीटर पानी की जरूरत होती है। यह मात्रा भार के हिसाल से घटती बढ़ती रहती है। आपके काम के हिसाब से भी पानी की मात्रा बढ़ या घट सकती है।

एक्सरसाइज के वक्त पीएं ज्यादा पानी

ज्यादा वर्कआउट करने वाले लोगों को पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है। इससे बॉडी में से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, ऐसे में पानी की कमी को रोकने के लिए थोड़े-थोड़े समय बाद पानी पीते रहे। पानी की जगह पर आप एनर्जी ड्रिंक,जूस,नींबू पानी और लस्सी का सेवन भी कर सकते हैं।

बारिश के मौसम में बच्चों का ऐसे रखें ख्याल

नहीं होगी कोई बीमारी

यूं तो बच्चों के लिए बारिश का मौसम और मानसून खूब सारी मस्ती लेकर आता है, लेकिन इस मौसम में बीमारियां भी काफी बढ़ती हैं. इस मौसम में बच्चों की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होता है. बारिश का सीजन में बच्चे कई सारी बीमारियों को न्यौता देते हैं, ऐसे में वो बीमार ना हो जाएं कुछ इस तरह उनका ख्याल रखें.

साफ पानी से धोएं खाद्य पदार्थ

बारिश के मौसम में जमीन में रहने वाले ज्यादातर कीड़े सतह पर आ जाते हैं, जो फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं. इसलिए किसी भी फल और सब्जियों को खाने से पहले साफ पानी से अच्छे से धोएं और अगर जरूरत हो तो बीमारी से बचने के लिए पोटैशियम परमेंगनेट का प्रयोग किया जा सकता है.

उबला हुआ पानी पिलाएं

बरसात में पानी के वजह से भी इंफेक्शन होता है, बच्चों को उबला हुआ पानी पिलाएं और खुद भी यही पिएं. साफ-सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें मच्छरों से बचने के लिए घर और आस-पास गंदगी न होने दें और जर्म्स रिपेलेंट लिक्विड का इस्तेमाल करें.

समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह लें

बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और बीमारियां उनपर जल्दी अटैक करती हैं. तो इस मौसम में बच्चों में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें. बारिश में बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को गंदगी से दूर रखें.

बच्चों को भींगने से बचाएं

बारिश में बच्चों को भीगने न दें. अगर वे स्कूल से लौटते वक्त भीग जाएं तो तुरंत उन्हें साफ पानी से नहालाएं और हीटर या आग से सर्दी को दूर करें. बच्चों के शरीर की साफ-सफाई का भी ध्यान रखें. साथ ही उनके खेलने की जगह को भी साफ रखें.

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

साइकिल चलेगी तो होंगे दंगे: सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीलीभीत में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, अगर साइकल चलेगी तो दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा, गुंडागर्दी होगी और गरीबों की जमीनों पर कब्जा होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने साइकल को पंचर कर दिया है और अब उसे चलने लायक नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्होंने 569.11 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बांग्लादेश से आए विस्थापित परिवारों को भूमि स्वामित्व के प्रमाण पत्र भी सौंपे. अब दुनिया की कोई ताकत इन विस्थापित परिवारों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि करीब 55-56 वर्ष पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण पूर्वी बंगाल से निकाले गए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध परिवार दशकों तक अपने अधिकारों के लिए भटकते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें सम्मान के साथ उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला है।

असम और अरुणाचल में बाढ़-बारिश से हाहाकार

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून सीजन में भारी बारिश ने तबाही मचाई है. अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने कई जिलों को प्रभावित किया है, जबकि असम में भी बाढ़ से स्थिति बिगड़ गई है. सड़कें धंस गई हैं. लोहे का 300 मीटर लंबा पुल बाढ़ में बह गया है. दोनों ही राज्यों के कई इलाकों में घर-मकान, सड़कें और खेतों में किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त है. अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों कुदरत का कहर बरपा है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है.आपदा के चलते राज्य में अब तक तीन मौतों की पुष्टि हुई है जबकि कई अन्य लापता हैं. IAF और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बहाव वाले पानी ने सबकुछ अपने साथ बहा लिया है. सड़कें, पुल बुरी तरह प्रभावित हैं।

यासीन मलिक समेत कई पर चार्जशीट दाखिल

नईदिल्ली। सालों पहले कश्मीर में एक नर्स की बेहद वहशी तरीके से हत्या कर दी गई थी. अब 35 साल बाद इस केस में सबसे बड़ी कार्रवाई की है. जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी स्ट्र ने श्रीनगर की झ्रष्ट कोर्ट में 700 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में छ्रुयस्र चीफ यासीन मलिक समेत कई लोगों का नाम शामिल है.ये मामला है 18 अप्रैल 1990 का. सरला भट नाम की एक नर्स श्रीनगर के स्ब्रह्व्स् हॉस्पिटल में काम करती थीं. इस दिन आतंकियों ने उन्हें हॉस्पिटल के पास से अगवा कर लिया. इसके बाद उनके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट, टॉर्चर और दुष्कर्म किया गया. फिर श्रीनगर के ओमर कॉलोनी, मालबाग इलाके में उन्हें गोलियों से भून दिया गया. ये उस दौर की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है, जब कश्मीर में आतंकवाद अपने शुरुआती और सबसे खतरनाक दौर में था।

कासगंज में प्रशिक्षण विमान क्रैश, महिला पायलट घायल

कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में विमान उड़ा रही महिला प्रशिक्षु पायलट घायल हो गई. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर किया गया है. हादसे के बाद प्रशासन और संबंधित एजेंसियां दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गई हैं. बता दें कि कासगंज में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्रशिक्षण उड़ान पर निकला एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट पुलिस लाइन के पीछे सिक्स-लेन हाईवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान के जमीन पर गिरते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए.हादसे में विमान उड़ा रही महिला प्रशिक्षु पायलट घायल हो गईं. स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और सूचना मिलते ही पुलिस तथा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. घायल पायलट को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है।

राहुल गांधी का सेक्रेटरी बन की 10 लाख की ठगी

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पर्सनल सेक्रेटरी बताकर फर्जी फंडरेजिंग के नाम पर हरियाणा के एक कांग्रेस नेता से 10 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. एफआईआर के मुताबिक, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर संजीव को 24 जनवरी को व्हाट्सएप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को राहुल गांधी का सेक्रेटरी कनिष्क सिंह बताया. आरोप है कि कॉलर ने कहा कि चंडीगढ़ में उत्तराखंड कांग्रेस यूनिट का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होना है और इसके लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है. इसी बहाने उसने कथित तौर पर 10 लाख रुपये की ठगी कर ली. पुलिस के मुताबिक, कॉल करने वाले ने कुरुक्षेत्र के भुकरी गांव निवासी संजीव से कहा कि पार्टी हाईकमान के कुछ सदस्य चंडीगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे. उन्हें होटल में ठहराने और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. साथ ही, कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कराने का भी भरोसा दिया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और सुरक्षा से बनेगा विकसित भारत

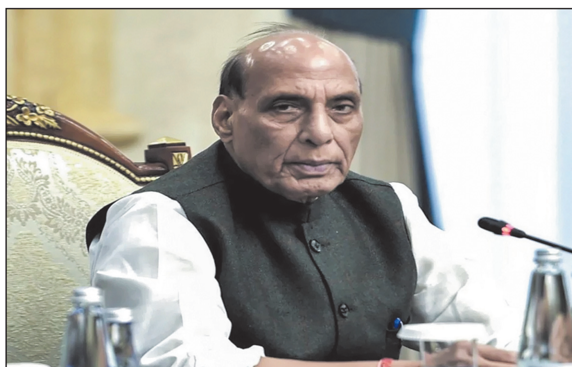

वडोदरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि वाइब्रेंट गुजरात प्लेटफ़ॉर्म एक देशव्यापी आंदोलन बन गया है जो विकसित भारत के विज़न में योगदान दे रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मज़बूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा मिलकर एक मज़बूत राष्ट्र की नींव बनाते हैं। वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि यह पहल नए विचारों और अवसरों के ज़रिए गुजरात को आगे बढ़ने में मदद कर रही है।

उन्होंने कहा यह नए विचारों और नई संभावनाओं के ज़रिए गुजरात को आगे ले जाने की कोशिश है। मैंने यहाँ लगी प्रदर्शनी भी देखी। इसमें इंडस्ट्री, एमएसएमई, आदिवासी उत्पादों और भारी उद्योगों सहित कई क्षेत्रों की भागीदारी है। रक्षा उद्योग में हो रहा काम भी तारीफ़ के काबिल है। आप हमें प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

देश के लिए गुजरात के योगदान की तारीफ़ करते हुए सिंह ने कहा कि राज्य ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कई महान नेता दिए हैं। उन्होंने कहा गुजरात ने देश को महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल दिए, और इसी धरती ने भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिए। जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है।

आज जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, तो दुनिया ध्यान से सुनती है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनका जन्म एक गुजराती माँ की कोख से हुआ था। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात पहल शुरू की थी, जो पिछले दो दशकों में एक बड़े आंदोलन में बदल गई है।

उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात मंच गुजरात के लोगों और उद्योगों की जीवंतता को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आज यह विकसित भारत के विज़न से जुड़ा एक व्यापक आंदोलन बन गया है। पिछले दो दशकों में इसने गुजरात में अभूतपूर्व बदलाव लाए हैं और आज गुजरात भारत का विकास इंजन बन गया है। सम्मेलन में अपनी भागीदारी के महत्व को समझाते हुए सिंह ने कहा कि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।

कुछ लोगों का यह पूछना स्वाभाविक है कि रक्षा मंत्री का वाइब्रेंट गुजरात से क्या लेना-देना है। एक मज़बूत अर्थव्यवस्था ही सुरक्षित राष्ट्र की नींव रखती है। रक्षा क्षेत्र का विकास केवल हथियार बनाने तक ही सीमित नहीं है; यह एक व्यापक आर्थिक इकोसिस्टम को भी गति देता है।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू

पांच राज्यों में घर-घर पहुंचेंगे अधिकारी

नई दिल्ली। देशभर में मतदाता सूची को दुरुस्त और अद्यतन करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक और मेघालय में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और अपात्र नामों को सूची से हटाया जा सके। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी।

इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और उनसे मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की पुष्टि कराएंगे। घर-घर जाकर सत्यापन का यह अभियान 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक और मेघालय में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। दिल्ली में 13 हजार से अधिक बीएलओ तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र में एक लाख से अधिक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। कर्नाटक में 59 हजार से अधिक बूथ स्तर अधिकारी इस अभियान में जुटे हैं, जबकि मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में 1,021 बीएलओ तैनात किए गए हैं। झारखंड में भी घर-घर गणना प्रपत्र वितरण का काम शुरू हो चुका है।

विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बीएलओ प्रत्येक घर पर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे। मतदाताओं को फॉर्म में दर्ज जानकारी की जांच करनी होगी और उसे भरकर बीएलओ को वापस देना होगा। मतदाता चाहें तो बीएलओ की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनका पहचान पत्र भी देख सकते हैं। यदि किसी घर पर बीएलओ के पहुंचने के समय ताला लगा मिलता है, तो अधिकारी फॉर्म छोड़कर जाएंगे और कम से कम तीन बार दोबारा वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं का नाम पहले से मतदाता सूची में है, उन्हें सामान्य तौर पर केवल अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी।

भगवंत मान के वायरल वीडियो पर महाविवाद

अकाल तख्त के फैसले के खिलाफ हुई पंजाब सरकार

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक वीडियो को लेकर बड़े विवाद में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर फैले इस वीडियो में एक आदमी सिख गुरुओं और पूजनीय हस्तियों की तस्वीरों के सामने हाथ में शराब का गिलास लिए दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि शराब के छींटे इन पवित्र तस्वीरों पर भी पड़े। इस बात से सिख संगठन और विरोधी पार्टियां बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि यह सिख गुरुओं का बड़ा अपमान है, क्योंकि सिख धर्म में पवित्र जगहों या धार्मिक तस्वीरों के पास शराब रखना बिल्कुल गलत माना जाता है।

यह मामला सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था अकाल तख्त के पास पहुंचा। वहां पांच सदस्यों की कमेटी ने इस मामले की जांच की। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह वीडियो सचमुच असली है और इसमें दिख रहा व्यक्ति भगवंत मान ही है? भगवंत मान ने कहा कि यह वीडियो असली नहीं है और इसे कंप्यूटर की मदद से बनाया गया है। लेकिन अकाल तख्त ने उनके इस दावे को गलत बताया। संस्था ने वीडियो को असली माना और भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया।

अकाल तख्त के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने कुछ जांच रिपोर्ट दिखाई। सरकार ने दावा किया कि इन रिपोर्टों के मुताबिक वीडियो नकली है और इसमें दिख रहा आदमी मुख्यमंत्री नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस आधार पर अकाल तख्त के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में पुलिस जांच में पता चला कि पंजाब सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की थीं, वे खुद नकली थीं। जिन लैब के नाम पर वे रिपोर्ट बनी थीं, उनका कोई अता-पता ही नहीं था।

इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और नकली रिपोर्ट बनाने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शक है कि इसमें पंजाब पुलिस के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान भी बदलते रहे। पहले उन्होंने इसे एआई से बना वीडियो बताया, तो बाद में कहा कि वीडियो में दिख रहा आदमी कोई और है, जिसने उनके जैसा दिखने वाला मुखौटा पहन रखा था। अब सरकार पर जनता और धार्मिक संस्थाओं को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं।

यह विवाद इसलिए भी बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि पंजाब सरकार ने हाल ही में धार्मिक अपमान को रोकने के लिए एक बहुत सख्त कानून पास किया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस नए कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने या इसकी साजिश रचने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का नियम है।

अब विरोधी दल यह सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार ने इतना सख्त कानून बनाया है, तो क्या मुख्यमंत्री पर आरोप साबित होने पर उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी? कानूनी तौर पर यह मामला थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि यह नया कानून मुख्य रूप से गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर लागू होता है, तस्वीरों के अपमान पर नहीं। साथ ही, कोई भी कार्रवाई करने से पहले कानूनी रूप से यह साबित करना होगा कि वीडियो में दिख रहा आदमी सचमुच मुख्यमंत्री ही है। राजनीति में अब इस बात पर बहस छिड़ी है कि क्या यह कानून सिर्फ आम जनता के लिए है या बड़े नेताओं पर भी लागू होगा।

खेल

प्रमुख समाचार

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच आज

नईदिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज हार के बाद भारतीय टीम वापसी की कोशिश करेगी, जबकि इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद पहली बार टी20 मैदान पर उतरेगा।

भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेलने उतर रहे बटलर सिर्फ 31 रन बनाते ही ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, जो आज तक कोई बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाया है।

जोस बटलर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 701 रन बनाए हैं। वहीं भारत के खिलाफ उनके नाम 669 रन दर्ज हैं। अगर वह पहले टी20 में 31 रन बना लेते हैं तो भारत के खिलाफ 700 रन पूरे कर लेंगे। इसके साथ ही बटलर टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने दो अलग-अलग देशों के खिलाफ 700 या उससे अधिक रन बनाए हों।

बटलर भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 25 पारियों में 669 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 31.85 और स्ट्राइक रेट 143.87 रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ पांच अर्धशतक भी जड़े हैं। भारत-इंग्लैंड टी20 मुकाबलों में भी सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बटलर के नाम है। उन्होंने विराट कोहली (648 रन) से 21 रन अधिक बनाए हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 250 अंक फिसला निफ्टी 80 अंक टूटा

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। आईटी और चुनिंदा बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स 249.70 अंक गिरकर 76,478.67 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 80.50 अंक यानी 0.34 फीसदी की गिरावट के साथ 23,865.75 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में आयचर मोटर्स, इंफोसिस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर सबसे ज्यादा दबाव में रहे। निवेशकों की नजर आज दोहा में होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता पर भी बनी रही, जिसका असर बाजार की धारणा पर देखने को मिला। कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में भी घरेलू शेयर बाजार दबाव में रहा। इसके चलते इस अवधि में निफ्टी करीब 8.6 फीसदी और सेंसेक्स 10.2 फीसदी तक गिर गया।

आलू-प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल

नईदिल्ली। देश के कई शहरों में एक बार फिर आलू-प्याज और टमाटर की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इन तीन चीजों की कीमतें बढ़ने से आगे आने वाले समय में खाने-पीने की चीजों की महंगाई यानी कि फूड इंफ्लेशन बढ़ने का डर अब लोगों को सताने लगा है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक, पिछले एक महीने में टमाटर की औसत रिटेल कीमत 18 फीसदी, प्याज की 11 फीसदी और आलू की 1.3 फीसदी बढ़ी है। साल-दर-साल के आधार पर देखें तो टमाटर की कीमतें 25 फीसदी और प्याज की कीमतें 3.3 फीसदी बढ़ी हैं, जबकि आलू की कीमतों में 17 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। बेमौसम बारिश से फसल के स्टोरेज की क्वालिटी पर असर पड़ने के बाद कई राज्यों में प्याज की कीमतें 10-20 फीसदी बढ़ी हैं।

आईसीआईसीआई बैंक के निवेशकों की होगी कमाई!

नईदिल्ली। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक के शेयर हैं या आप डिविडेंड पाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। यानी अब यह तय हो गया है कि किन शेयरधारकों को डिविडेंड मिलेगा। बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि 3 अगस्त 2026 को डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया है। इसका मतलब है कि इस तारीख तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में शेयरधारक के तौर पर दर्ज होंगे, वही डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। हालांकि, डिविडेंड की अंतिम मंजूरी बैंक की सालाना आम बैठक (एजीएम) में मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने इस साल 12 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की सिफारिश की है।

पीएसयू बैंकों ने भरी सरकार की तिजोरी

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कुल 9,439 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में दिए हैं। केनरा बैंक के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ब्रजेश कुमार सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 2,397 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक सौंपा। इस अवसर पर वित्तीय सेवा सचिव संजय लोहिया भी मौजूद रहे। केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 4.20 रुपए का लाभांश घोषित किया है, जो दो रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर का 210 प्रतिशत है। पीएनबी के प्रबंध निदेशक और सीईओ अशोक चंद्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 2,416 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा।

उदारीकरण के 35 साल बाद भी विनिर्माण में पिछड़ा भारत

नितिन देसाई

लगभग 35 वर्ष पहले वर्ष 1991 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट पेश किया था जिसने औद्योगिक लाइसेंसिंग का अंत करते हुए 'उदारीकरण' वाले सुधारों की शुरुआत की थी। यद्यपि उसे 'निजीकरण' सुधारों के रूप में अधिक जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सरकारी क्षेत्र से निजी उद्योगों की ओर बदलाव को देखा जा सकता था। शायद इसका सबसे अहम इरादा था विनिर्माण में वृद्धि को रफ्तार देना। सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण की हिस्सेदारी में वृद्धि भी देखने को मिली और 1995-96 तक यह वर्तमान मूल्यों पर बढ़कर 19.7 फीसदी हो गया। परंतु यह अस्थायी कामयाबी थी।

तब से जीवीए में विनिर्माण की हिस्सेदारी 17-18 फीसदी के आसपास बनी रही और 2011-12 में यह 17.4 फीसदी रही। इसके बाद इसमें गिरावट आने लगी और 2023-24 में यह घटकर 14.3 फीसदी पर आ गई जो 1974-75 में हासिल स्तर से भी 3 फीसदी कम था।

यह गिरावट सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में विनिर्माण की हिस्सेदारी में कमी से भी मेल खाती है जो 2011-12 में 40.8 फीसदी से घटकर 2023-24 में 31.6 फीसदी रह गई। और भी चिंताजनक तथ्य यह है कि रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी 1990-91 से लेकर अब तक 10 फीसदी से थोड़े अधिक पर स्थिर बनी हुई है।

वैश्विक विकास सूचकांक दिखाते हैं कि वर्ष 2024 में भारत में वर्तमान डॉलर में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिशत के रूप में विनिर्माण मूल्यवर्धन का हिस्सा 12.6 फीसदी था।

यह हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश (21.9

फीसदी) और श्रीलंका (17.6 फीसदी), दक्षिण-पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया (19.0 फीसदी), मलेशिया (22.5 प्रतिशत), थाईलैंड (24.3 प्रतिशत) और वियतनाम (24.4 फीसदी) तथा पूर्वी एशियाई राष्ट्र चीन (24.9 फीसदी) और दक्षिण कोरिया (26.6 फीसदी) से स्पष्ट रूप से कम है। चीन के साथ तुलना सबसे उल्लेखनीय है। वर्ष 1990 में चीन और भारत के विनिर्माण आधार लगभग समान थे। लेकिन 2025 तक चीन का विनिर्माण मूल्य वर्धन भारत से लगभग 10 गुना बड़ा हो गया। स्पष्ट रूप से जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी में भारत और अधिकांश एशियाई देशों के बीच यह बड़ा अंतर इस बात का संकेत है कि हमारे यहां विनिर्माण प्रोत्साहन नीति पर्याप्त नहीं रही है।

भारत के सामने वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण विकास चुनौती विनिर्माण वृद्धि को नई गति देना और 25 फीसदी लक्ष्य हासिल करने की संभावना बढ़ाना है जिसे पहली बार 2012 में व्यक्त किया गया था और 2015 तथा 2025 की नीतिगत घोषणाओं में दोहराया गया। सच्चाई यह है कि विनिर्माण विकास का निजीकरण नए उद्यमियों के लिए उस तरह के अवसर नहीं पेश कर पाया जिस कि उदारीकरण से अपेक्षित था। स्थापित औद्योगिक समूह फले-फूले और अपनी मौजूदगी का विस्तार करते रहे।

सरकारी हस्तक्षेप को व्यवसाय-हितैषी होने से बाजार-हितैषी होने की ओर बढ़ना चाहिए। यह 1991 में शुरू किए गए 'उदारीकरण' बदलाव के साथ अधिक सुसंगत होगा। हमारी वर्तमान नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त होने के बाद भी उद्यमिता चयन शामिल है और विनिर्माण में उत्पादन संबद्ध पहल (पीएलआई) जैसे समर्थन कार्यक्रमों में यह जारी है। इनमें से अधिकांश बहुक्षेत्रीय समूहों के पक्ष में हैं। सरकार और कुछ उद्यमों के बीच यह संबंध अन्य लोगों को संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धा करने से हतोत्साहित करता है।

महत्वपूर्ण संरचनात्मक विकास के लिए उस चीज की आवश्यकता होती है जिसे जोसेफ शुम्पीटर ने 'रचनात्मक विनाश' कहा था। सार्वजनिक नीति में स्थापित उद्यमों को समर्थन देना इसके विपरीत काम करता है। उद्यमिता की सफलता के लिए कॉरपोरेट प्रबंधकों, अफसरशाहों या मंत्रियों के बीच किसी करीबी संबंध की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा को रोक सकता है।

मुख्यमंत्री साय की गरिमामयी उपस्थिति में रामगढ़ महोत्सव-2026 का भव्य समापन

रामगढ़ में रामायण की स्मृतियां आज भी जीवंत

रायपुर। रामगढ़ केवल एक सांस्कृतिक आयोजन का केंद्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, प्रकृति पूजा, आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। सरगुजा की यह पवित्र भूमि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में रामगढ़ का उल्लेख मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को प्रमाणित करता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के ऐतिहासिक दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनश्रुतियों के अनुसार त्रेतायुग में वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस क्षेत्र में समय व्यतीत किया था। सीताबेंगरा गुफा आज भी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है तथा रामगढ़ की हवाओं और शिलाओं में रामायण की स्मृतियां आज भी जीवंत हैं।

उन्होंने कहा कि सीताबेंगरा गुफा भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक मानी जाती है, जहां हजारों वर्ष पूर्व सांस्कृतिक आयोजन और नाट्य प्रस्तुतियां होती थीं। वहीं जोगीमारा गुफा अपनी प्राचीन भित्तिचित्र कला के लिए विश्वविख्यात है। हाथीपोल जैसी प्राकृतिक शैल संरचना तथा यहां के प्राचीन शिल्प हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकवि कालिदास द्वारा मेघदूतम् की रचना इसी क्षेत्र में किए जाने का उल्लेख मिलता है, जिससे रामगढ़ का साहित्यिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार रामगढ़, सीताबेंगरा और जोगीमारा जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित हो सकें। उन्होंने कहा कि जिस भव्यता के साथ इस वर्ष रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ है, उसी भव्यता के साथ यह महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरगुजा जिले में 2,387 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में लोगों के पक्के आवास का सपना तेजी से साकार हो रहा है। 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रतिदिन लगभग 1,600 आवास बनकर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। पुनर्वासित नक्सलियों तथा विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। 13 लाख किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1,000 रुपये अंतरित किए जा रहे हैं। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 49 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराया गया है। तीर्थयात्रा दर्शन योजना के अंतर्गत देश के 19 प्रमुख तीर्थस्थलों को शामिल किया गया है, जहां वरिष्ठ नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में लगातार भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

सिम्स बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता का नवीनीकरण

■ एनएमसी ने जारी किया लेटर ऑफ रिन्यूअल, प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा नया आयाम

रायपुर । राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), नई दिल्ली के स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थानकी 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता का नवीनीकरण जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में 150 विद्यार्थियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

यह उपलब्धि सिम्स में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा, आधुनिक आधारभूत संरचना, अनुभवी संकाय तथा मरीजों को प्रदान की जा रही उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाण है। एनएमसी द्वारा जारी यह नवीनीकरण संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता, गुणवत्ता मानकों के सफल अनुपालन एवं निरंतर प्रगति की राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि करता है।

सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता का नवीनीकरण पूरे सिम्स परिवार के लिए गौरव का विषय है। यह संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता, समर्पित शिक्षकों, आधुनिक संसाधनों और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को मिली राष्ट्रीय मान्यता है। सिम्स को मध्य भारत के अग्रणी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, आधुनिक अधोसंरचना तथा उत्कृष्ट नैदानिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। उन्होंने बताया कि सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा शासकीय चिकित्सा संस्थान है, जहाँ प्रतिदिन लगभग 2,000 से 2,500 मरीज बाह्य रोगी विभाग में उपचार के लिए पहुँचते हैं तथा लगभग 900 मरीज विभिन्न वार्डों में भर्ती रहकर उपचार प्राप्त करते हैं। संस्थान में 24 घंटे संचालित ब्लड बैंक, अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर एवं विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी विभागों के माध्यम से उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं, लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करें विद्यार्थी: मंत्री देवांगन

■ नव प्रवेशी विद्यार्थियों का किया गया अभिनंदन, वितरित की गई अध्ययन सामग्री

रायपुर । प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में आज कोरबा विकासखंड के ग्राम भैंसमा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, पुष्प भेंट कर एवं मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष कोरबा मती बीजमोती राठिया, अध्यक्ष करतला जनपद मती अशोका विश्राम कंवर, जिला पंचायत सदस्य मती रेणुका राठिया, उपाध्यक्ष जनपद करतला मनोज झा, कलेक्टर कुणाल दुदावत, सहायक कलेक्टर ईशान जायसवाल, सीईओ दिनेश नाग, डीईओ टी पी उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं स्कूली बच्चे व पालक उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत से अतिथियों का अभिनंदन किया व आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने सभी विद्यार्थियों को नवीन शैक्षणिक सत्र के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया सत्र नई ऊर्जा, नए संकल्प और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता। यह जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है, जिसका कभी बंटवारा नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत और लगन से अध्ययन करें।

1070 सम्पतियों से डेढ़ करोड़ से अधिक की राजस्व वसूली

रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर 29 जून सोमवार को रायपुर नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार 1 करोड़ रूपये से भी अधिक 1070 सम्पतियों से 1 करोड़ 55 लाख 63119 रूपये का राजस्व वसूला गया। सभी व्यबसायिक सम्पतियों की जाँच कर सही टेक्स निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैँ। जोन 3 ने 90 सम्पतियों से 10 लाख 98 हजार 438 रूपये की राजस्व वसूली की. वंहीं आज जोन 4 ने 90 सम्पतियों से 20 लाख 85000 रूपये की राजस्व वसूली की इसी प्रकार जोन 5 ने 119 सम्पतियों से 15 लाख 3 हजार 842 रूपये, जोन 7 द्वारा 64 सम्पतियों से 11 लाख 1 हजार 159 रूपये, जोन 8 जोन द्वारा 120 सम्पतियों से 18 लाख 96

हजार 579 रूपये, जोन 9 द्वारा 196 सम्पतियों से 20 लाख 55 हजार 499 रूपये, जोन 10 द्वारा 136 सम्पतियों से 12 लाख 6 हजार 619 रूपये का राजस्व 29 जून सोमवार को वसूला गया। उल्लेखनीय है कि 30 जून तक वित्त वर्ष 2025-26 के देय सम्पतिकर की राशि की पूर्ण अदायगी करने वाले सम्पति करदाता नागरिकों को सम्पतिकर की राशि में अधिकतम 6⁼25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

प्रशासन 'औद्योगिक सुरक्षा, श्रमिक हित और पर्यावरणीय मानकों के पालन में सख्त'

रायपुर। औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा, पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन तथा वैधानिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त निरीक्षण अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा पर्यावरणीय मानकों के पालन का विस्तृत परीक्षण किया।

संयुक्त दल में तहसीलदार रायगढ़, उप संचालक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सहायक संचालक उद्योग तथा पर्यावरण विभाग के अधिकारी शामिल थे। टीम ने इमुल टेक, रिजेनेसिस इंडस्ट्रीज़ सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रबंधन, श्रमिकों के लिए अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों तथा पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देते हुए संबंधित प्रबंधन को निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा तथा पर्यावरणीय नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।जिला प्रशासन के अनुसार, पूर्व में किए गए निरीक्षणों के दौरान जारी कारण बताओ नोटिस के बाद शिव शक्ति स्टील प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री साईं गणेश ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके फलस्वरूप दोनों औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध माननीय श्रम न्यायालय, रायगढ़ में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रशासन ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेग।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ रायपुर जिला की पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी की घोषणा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी के निर्देशानुसार तथा प्रदेश संगठन के मार्गदर्शन में, संभाग प्रभारी डॉ. अनुज खरे, सह-संभाग प्रभारी डॉ. अजय गजेंद्र एवं प्रदेश संयोजक डॉ. देवेंद्र कश्यप की सहमति तथा भाजपा रायपुर जिला अध्यक्ष माननीय रमेश सिंह ठाकुर की अनुशंसा पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ रायपुर जिला संयोजक डॉ. सत्येंद्र पाण्डेय द्वारा चिकित्सा प्रकोष्ठ रायपुर जिला के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी की घोषणा की गई।इस अवसर पर भाजपा रायपुर जिला के उपाध्यक्ष अकबर अली भी उपस्थित रहे। जिला संयोजक डॉ. सत्येंद्र पाण्डेय ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी पदाधिकारी संगठन की रीति-नीति के अनुरूप कार्य करते हुए जनसेवा, स्वास्थ्य जागरूकता एवं संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

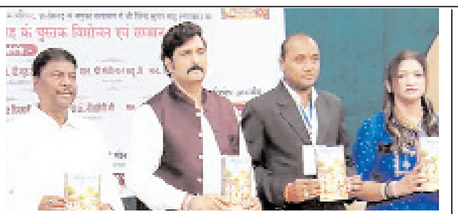

रायपुर में मोर अंगना के शोर पुस्तक का विमोचन

रायपुर। वृंदावन हाल में मोर अंगना के शोर नामक पुस्तक का विमोचन प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने किया. मोर अंगना के शोर पुस्तक 25 जिलों के 50 से अधिक नवाचारी शिक्षक और साहित्यकारों के सामूहिक प्रयास से तैयार की गई है. इस पुस्तक में 121 बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है. छत्तीसगढ़ में बाल साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है.

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हमारे चिन्हारी साहित्य समिति छत्तीसगढ़ एवं साहित्य लेखन रिसोर्स शिक्षक परिवार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था. पुस्तक को बालवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है. इसके संपादक वीरेंद्र कुमार साहू है।प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस पुस्तक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है. मोर अंगना के चिन्हारी साहू जी ने इसको संकलित किया है. पूरे राज्य के लगभग 25 जिलों के शिक्षकों ने सहयोग दिया है. अपने प्रकृति संस्कृति जो जुड़ाव है।

प्रदेश में फिर चरण पादुका घोटाला: दीपक बैज

रायपुर। भाजपा सरकार एक बार फिर चरण पादुका घोटाला करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहा कि सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए जूता खरीदने के लिए जो टेंटर निकाली है उससे साफ हो रहा है कि सरकार एक बार फिर गरीबों के जूतों के नाम पर कमीशनखोरी का रास्ता तैयार कर रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए जो जूते खरीदने का टेंडर बुलाया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि संग्राहकों हेतु ''सेफ्टी-शू'' की आवश्यकता है। सेफ्टी-शू के लिए निविदा बुलाई गयी है। सेफ्टी-शू की बनावट इस प्रकार होती है कि उसे पहन कर संग्राहक सुचारू रूप से चल-फिर नहीं पायेंगे। सेफ्टी-शू सामान्य से ऊंची हील और घुटने तक उसका कालर होता है जबकि संग्राहकों को सामान्य ''वाकिंग-शू'' की जरूरत होती है जिसे पहन क रवह संग्रहण के साथ अपना रोजमर्रा का काम कर पायें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बताया जाता है कि मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा नेता जो केंद्र में मंत्री भी है उनके परिजनों को जूता सप्लाई का काम देने के लिए टेंडर में ''सेफ्टी-शू'' की शर्त डाली गयी है। सरकार ने इस हेतु लगभग 12.5 लाख जूता जिनकी लागत लगभग 50 करोड़ रू. होती है कि निविदा बुलाया है।

राजेश मूणत ने किया मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हो रहे विकास कार्यों और मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की पहल के अंतर्गत पंडित रामदयाल तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 29 मेधावी विद्यार्थियों को ?5-5 हजार के प्रोत्साहन चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1.50 करोड़ की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा खेल मैदान के विकास के लिए 19 लाख की स्वीकृति की जानकारी भी दी गई। इन कार्यों से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, सुविधाजनक कक्ष और खेल गतिविधियों के लिए उपयुक्त मैदान उपलब्ध होगा।

कृषि विवि में कर्मचारियों को दी गई भावभीनी विदाई

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. एम.पी. ठाकुर सहित चार कर्मचारियों को आज यहां भावभीनी विदाई दी गई। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह में पूर्व में निदेशक शिक्षण, निदेशक विस्तार सेवाएं तथा अधिष्ठाता कृषि संकाय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके डॉ. एम.पी. ठाकुर को उनकी अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर विदाई दी गई। डॉ. ठाकुर सेवानिवृत्ति से पूर्व कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नोडल अधिकारी का दायित्व संभाल रहे थे। छत्तीसगढ़ में मशरूम की खेती को गांव-गांव तक पहुंचाने में डॉ. ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके अलावा निदेशक शिक्षण कार्यालय से सेवानिवृत्त तीन अन्य कर्मचारियों श्री मुक्तानंद नायक शाखा अधिकारी, श्री जलम यादव सहायक ग्रेड-01 एवं श्री नवल किशोर श्रीवास्तव वाहन चालक को भी भावभीनी विदाई दी गई। कुलपति डॉ. चंदेल ने सभी सेवानिवृत्त होने वालों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने उनके सेवानिवृत्ति उपरांत स्वस्थ, सुदीर्घ तथा सुखमय जीवन हेतु शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

छत्तीसगढ़ कंडरा आदिवासी समाज के सामाजिक भवन का हुआ लोकार्पण

शासकीय योजनाओं से मिल रहा सशक्त आधार: कश्यप

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप आज रायपुर के महादेव घाट में आयोजित छत्तीसगढ़ कंडरा आदिवासी समाज के सामाजिक भवन लोकार्पण, सम्मान समारोह एवं वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण किया और शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं प्रतिभाओं को सम्मानित किया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक ताकत उसकी शिक्षा, संगठन और संस्कार होते हैं। आज आदिवासी समाज के युवा शिक्षा, प्रशासन, तकनीक, व्यवसाय, खेल और जनप्रतिनिधित्व सहित अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। यह नए और विकसित होते छत्तीसगढ़ का सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि आज दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासी युवा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि बनकर समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।

मंत्री कश्यप ने कहा कि सामाजिक भवन केवल एक भवन नहीं, बल्कि समाज की एकता, संवाद, संस्कार और नई पीढ़ी के मार्गदर्शन का केंद्र है। यहां विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक कार्यक्रमों और समाज के विकास से जुड़े कार्यों के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास, वनाधिकार, स्वरोजगार, लघु वनोपज का बेहतर मूल्य तथा महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण जैसी योजनाओं से आदिवासी समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्री केदार कश्यप ने समाज के वरिष्ठजनों से अपनी समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, डिजिटल तकनीक और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की अपील की।कार्यक्रम के अंत में मंत्री केदार कश्यप ने सामाजिक भवन के निर्माण के लिए समाज को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि संगठित समाज, शिक्षित युवा और सशक्त नेतृत्व के बल पर छत्तीसगढ़ कंडरा आदिवासी समाज विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

राज्य शासन की भूमि आवंटन प्रक्रिया में आएगी तेजी: राजस्व मंत्री

रायपुर। राज्य शासन ने विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, सहकारी बैंकों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए शासकीय भूमि आवंटन से जुड़े मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण की दिशा में एक बड़ी पहल की है। इसी कड़ी में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में शासकीय भूमि आवंटन संबंधी विचारार्थ अंतरविभागीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। यह उच्च स्तरीय बैठक राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी के मार्गदर्शन में विचारार्थ प्रकरण सूची पर विस्तार से चर्चा की गई। 12 महत्वपूर्ण मामलों पर मंथनरू बैठक के दौरान कुल 12 प्रमुख प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें मुख्य रूप से आवासीय प्रयोजन, बैंक शाखा भवन, सामाजिक भवन, विद्यालय, ऑडिटोरियम निर्माण और विभिन्न संस्थाओं को शासकीय भूमि आवंटन से जुड़े मामले शामिल हैं।

बैठक में रायपुर, धमतरी, कवर्धा और जगदलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त भूमि आवंटन संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत विभागीय परीक्षण रिपोर्ट, आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र , ऑडिट संबंधी दस्तावेज एवं अन्य विधिक अभिलेखों का बारीकी से परीक्षण किया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.